सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 182, नई दिल्ली, बुधवार 10 सितंबर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय लेना, बाकी सब केवल दृढ़ता है...

03 दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, एस.बी.के. सिंह को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी
06 एमबीबीएस का विकल्प
08 स्तनपान सप्ताह: संकोच तोड़ने और सम्मान जोड़ने का अभियान

परिवहन विभाग दिल्ली तकनीकी या गैर तकनीकी विभाग ?

संजय बाटला

उपराज्यपाल दिल्ली, दिल्ली सरकार और परिवहन आयुक्त दिल्ली के अनुसार दिल्ली परिवहन विभाग गैर तकनीकी विभाग,

दिल्ली परिवहन आयुक्त ने अपने पद की शक्ति का मनमाना प्रयोग करते हुए ₹माननीय सुप्रीम कोर्ट, सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, माननीय कैट, कानून न्याय एवं निधि विभाग दिल्ली सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राजपत्र अधिसूचना के साथ मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) के पद के लिए भर्ती नियम (आर.आर)₹ को पूर्ण रूप से दरकिनार कर सभी तकनीकी पदों पर अपनी इच्छानुसार अपने प्रिय गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। (आपकी जानकारी हेतु राजपत्र अधिसूचना की प्रति सलग्न)

आपकी जानकारी हेतु बता दें एमवीआई पद के स्थान और भर्ती के लिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, और कुछ अनुभव शामिल होते हैं।

योग्यताएं (उदाहरण)

शैक्षिक योग्यताः किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री।

ड्राइविंग लाइसेंसः गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है।

कंप्यूटर ज्ञानः कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।

अनुभवः कुछ राज्यों में, मोटर वाहन निरीक्षक या सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक हो सकता है।

*दिल्ली भारत की राजधानी में परिवहन आयुक्त के नियमों और कानून के अनुसार दिल्ली परिवहन विभाग में एमवीआई, एमएलओ, डीटीओ के पदों पर आसीन होने के लिए किसी भी तकनीकी ज्ञान या अनुभव की आवश्यकता नहीं है कोई भी व्यक्ति इस पदों पर आसीन किया जा सकता है और ऐसा कर भी दिखाया। आज दिल्ली परिवहन विभाग के जितने भी तकनीकी पद है उनमें 70 % से अधिक पदों पर गैर तकनीकी अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

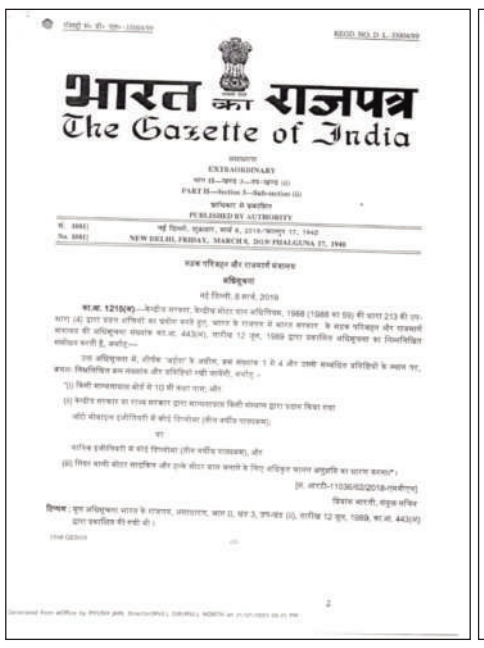

दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों एवं उनमें होने वाले किसी भी प्रकार के तकनीकी बदलाव की जांच तकनीकी अधिकारी से नहीं अपितु गैर तकनीकी अधिकारी से

जल्द दिल्ली में दिखेगी दौड़ती हुई डबल डेकर बसे

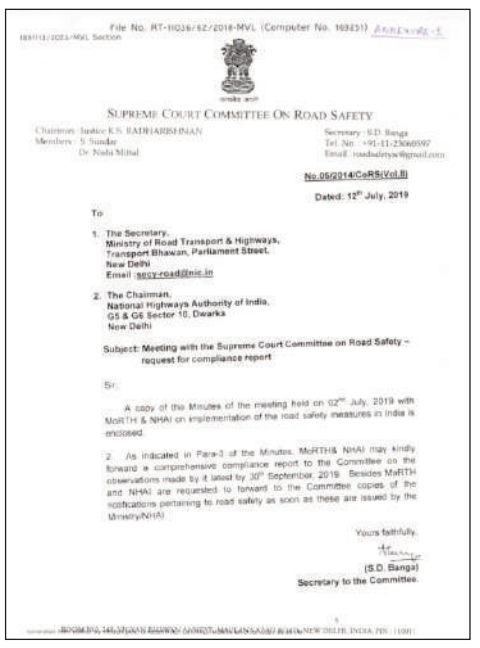

पूर्व समय में दिल्ली की सड़को पर खतरनाक हादसों में जुडी होने के कारण बंद की जाने वालीं डबल डेकर बसे दुबारा जल्द ही दिल्ली की सड़को पर दौड़ती नजर आएगी।

विश्वस्त सूत्रों की माने तो स्विच कंपनी द्वारा निर्मित डबल डेकर बस दिल्ली परिवहन निगम के डिपो में ट्रायल के लिए आ चुकी हैं।

दिल्ली में डबल डेकर बस और स्लीपर कोच के पंजीकरण अब तक बंद थे पर अब लगता हैं की दिल्ली में परिवहन निगम ही डबल डेकर बसे चलाने जा रहा है तो दिल्ली की जनता को दिल्ली में पंजीकृत स्लीपर कोच भी उपलब्ध होने लगेगे।

अभी तक दिल्ली में स्लीपर कोच सिर्फ परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस की अनुमति से चल रहे थे जिसे पूर्व में रहे परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा द्वारा पार्किंग के नाम से कश्मीरी गेट बस अड्डे के अंदर जाने का रास्ता दे दिया गया था पर अब दिख रहा है की कार्यरत परिवहन आयुक्त उन्हें दिल्ली में कानूनी तरीके से चलने की अनुमति भी जल्द दे देगी।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

Supreme Court Committee On Road Safety

डबल डेकर बसों के पंजीकरण पर लगी पाबंदी के ही कारण स्लिपर कोच को दिल्ली में बैन माना जाता रहा था जिसके चलते दिल्ली परिवहन विभाग ने बिहार परिवहन कॉर्पोरेशन तक की स्लिपर कोच को दिल्ली में चलने देने की इजाजत नहीं दी थी पर अब दिल्ली परिवहन आयुक्त की मेहरबानी से परिवहन विभाग तकनीकी अधिकारियों की जगह गैर तकनीकी अधिकारियों द्वारा चलवाया जा रहा है जिसके रहते किसी भी तकनीकी जांच की आवश्यकता ही नहीं रही तो पूर्व में लगी सभी पाबंदी खत्म कर इजाजत दी जा सकती हैं।

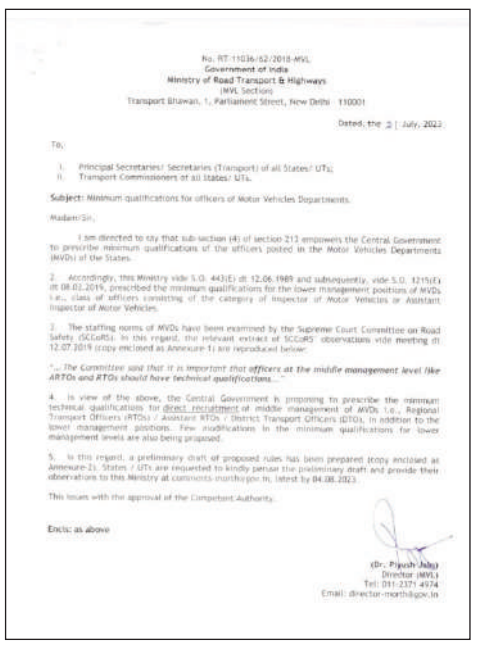

शायद इन्हीं बातों को देखते हुए परिवहन आयुक्त द्वारा तकनीकी पदों पर सर्विस रुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, माननीय कैट एवम्₹कानून, न्याय और विधायी मामलों का विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को दरकिनार कर गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है।

परिवहन आयुक्त, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दिल्ली का यह मानना है की दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों की जांच किसी तकनीकी अधिकारी से करवाने कि आवश्यकता ही नहीं है इसलिए दिल्ली की जनता को भी अब यह मान लेना चाहिए की दिल्ली परिवहन विभाग तकनीकी नहीं गैर तकनीकी विभाग है और वाहनों की भी तकनीकी जांच की आवश्यकता नहीं।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

------ साइबर सुरक्षा विचार ------

पिंकी कुंडू सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ
दिल्ली प्रदेश भाजपा

नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंधों के चलते हुए संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अब केवल बैकअप के रूप में नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति, जनसंपर्क और शासन के लिए एक स्वदेशी, सशक्त डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए।

भारत की विविधता, पैमाने और भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक, चरणबद्ध रोडमैपः

,स्वदेशी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए रोडमैप

चरण 1: रणनीतिक आधार

1. नीति और दृष्टिकोण की घोषणा

2. MeitY के तहत "डिजिटल संप्रभुता मिशन" की शुरुआत

स्वदेशी प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देशः डेटा स्थानीयकरण, बहुभाषीय पहुंच, और नैतिक AI, ऑडिट और अंतर विश्लेषण, सरकारी, मीडिया और नागरिक जुड़ाव क्षेत्रों में विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता का मूल्यांकन

प्रमुख कमजोरियों की पहचान (जैसे अचानक प्रतिबंध, डेटा लीक, गलत सूचना), बीज निधि और प्रोत्साहन

"स्वदेशी टेक इनोवेशन फंड" स्थापित करना

स्टार्टअप्स को टैक्स छूट, क्लाउड क्रेडिट और त्वरित अनुमोदन देना

चरण 2: प्लेटफॉर्म विकास और पायलट

प्लेटफॉर्म प्रकार	स्वदेशी उदाहरण	प्रमुख विशेषताएँ
मैसेजिंग ऐप	Sandes, BlueEra	एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन, सरकारी स्तर की सुरक्षा
माइक्रोब्लॉगिंग	Lok Samvaad	क्षेत्रीय भाषा समर्थन, सत्यापित हैंडल
वीडियो शेयरिंग	Chingari, Koo	क्रिएटर मोनेटाइजेशन, भारत-केंद्रित कंटेंट
सुपर-ऐप	i.AI, BlueEra	सोशल + कॉमर्स + नौकरियाँ + सुरक्षित मैसेजिंग

बहुभाषीय और स्थानीय प्राथमिकता हिंदी, तमिल, बंगाली, भोजपुरी और जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देना

AI आधारित अनुवाद और वॉयस इंटरफेस से पहुंच बढ़ाना

सार्वजनिक क्षेत्र में अपनाना

नागरिक सेवाओं, पुलिस आउटरीच और आपातकालीन अलर्ट के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म का अनिवार्य उपयोग

MyGov और डिजिटल इंडिया से एकीकरण

चरण 3: इकोसिस्टम विस्तार और लचीलापन

क्रिएटर और नागरिक प्रोत्साहन प्रभावशाली व्यक्तियों, शिक्षकों और आउटरीच अधिकारियों के लिए "डिजिटल स्वदेशी फैलोशिप" शुरू करना

क्षेत्रीय क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन टूल्स और प्रशिक्षण देना

साइबर सुरक्षा और विश्वास

राष्ट्रीय डिजिटल नैतिकता बोर्ड की स्थापना

रियल-टाइम मॉडरेशन, गलत सूचना अलर्ट और शिकायत निवारण को एकीकृत करना

वैश्विक निर्यात रणनीति

i.AI जैसे प्लेटफॉर्म को दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के डिजिटल निर्यात के रूप में प्रस्तुत करना

BIMSTEC और SAARC देशों के साथ सहयोग

आपातकालीन प्रोटोकॉल (हमेशा सक्रिय)

त्वरित प्रतिक्रिया ढांचा

नेपाल जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म प्रतिबंध की स्थिति में 48 घंटे के भीतर स्वदेशी विकल्प सक्रिय करना

कानून प्रवर्तन, मीडिया और नागरिकों के लिए संचार की निरंतरता सुनिश्चित करना

ऑफलाइन और मेश क्षमताएँ

आपदा क्षेत्रों या इंटरनेट बंदी के लिए पीयर-टू-पीयर मेश मैसेजिंग ऐप्स विकसित करना

आधार और डिजी लॉकर से पहचान सत्यापन का एकीकरण

यह रोडमैप केवल तकनीक का नहीं, बल्कि विश्वास, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक प्रासंगिकता का प्रतीक है।

नागपुर शहर के विकास को देखते हुए ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक आदेश पारित किया गया

परिवहन विशेष न्यूज

नागपुर शहर के विकास को देखते हुए ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार सभी तरह के भारी वाहनों पर नागपुर शहर के अंदर आने जाने पर सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक NO ENTRY लगाई गई है और आदेश का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसी विषय पर वाड़ी, वड़धामना के सभी ट्रांसपोर्टर्स व MIA के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई जिस में इस NO ENTRY से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।

सभी ने सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जताई कि शहर के विकास के लिए NO ENTRY जरूरी है लेकिन जिस तरीके से NO ENTRY लगाई गई है उस से MIDC हिंगना के सभी उद्योग व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होंगे क्योंकि नागपुर शहर की सीमा के अंदर MIDC जरूर है लेकिन MIDC हिंगना अमरावती रोड़ पर एक कोने में स्थित है इसलिए सभी की मांग है कि MIDC हिंगना में आने वाले वाहनों को गोंड़खैरी से वाड़ी की तरफ आते हुए वाड़ी T POINT से MIDC हिंगना में आने की छूट मिलनी चाहिए और वाड़ी T पॉइंट या दाभा के पास चेक पॉइंट लगाना चाहिए ताकि जो वाहन नए रिंग रोड़ का टोल टैक्स बचाने के लिए नागपुर शहर के अंदर आते हैं उनको रोका जा सके।

इसके साथ साथ सभी ने इस बात पर भी सहमति जताई कि इस नए आदेश के कारण जो गाड़ी MIDC में कांटा करवाने या लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगी उसको भी NO ENTRY वाला चालान देना पड़ सकता है तो वो भी अव्यवहारिक है क्योंकि MIDC हिंगना में कई फैक्टरियां ऐसी भी हैं जिनके 2/3 यूनिट्स है और अलग अलग यूनिट से अलग अलग माल लोड़ होता है तो अगर पूरा दिन MIDC हिंगना में गाड़ी नही चल पाएगी तो लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी और इस से MIDC हिंगना के उद्योग धंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

विचारणीय विषय ये भी है कि प्रशासन ने गोंड़खैरी में जो CHECK POINT लगाया है वहां ड्राइवर्स के लिए किसी भी तरह की पार्किंग, भोजन या शौचालय की सुविधा भी नही है और MIDC हिंगना की तरफ आने वाली गाड़ियाँ अगर सुबह 06 से रात 10 बजे तक इस नेशनल हाईवे पर रोक दी जाएंगी तो उनकी संख्या लगभग 500 के आस पास रहेगी और इतनी ज्यादा गाड़ियों के नेशनल हाईवे के किनारे पर खड़ा होने से जाम या दुर्घटना की स्थिति बनना स्वाभाविक है।

अतः जल्द ही इस विषय पर MIA व सभी ट्रांसपोर्टर्स उच्च अधिकारियों से मिल कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे व इस NO ENTRY के विषय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करेंगे।

इस अवसर पर MIA प्रेजिडेंट मा.मोहन जी के साथ MIDC हिंगना के काफी उद्यमी व ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से संबंधित किताब सिंह जी, महेंद्र शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, विमलेश सिंह, अखिलेश सिंह, राकेश अग्रवाल, नरेंद्र मिश्रा, नवीन शर्मा, वीरेंद्र मोर, आशीष पांडेय, अभय पटेल आदि काफी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी उपस्थित रहे और सभी ने जल्द से जल्द इस विषय के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की बात कही।

पिकअप और बाइक की भिड़ंत में युवक गंभीर रूप से हुए घायल

परिवहन विशेष न्यूज

जनपद बदायूं के थाना बिनावर छेत्र रफियाबाद मोड़ के पास हादसा, पिकअप चालक फरार, इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहम्मद उमर और फरमान सड़क किनारे जा गिरे। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार पिकअप लेके

रफियाबाद मोड़ के पास हादसा, पिकअप चालक पिकअप लेके फरार बिनावर- बिलहत मार्ग रफियाबाद पर जुमा को बिनावर थाना क्षेत्र के रफियाबाद मोड़ के पास एक तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार मोहम्मद उमर और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहम्मद उमर और फरमान बिनावर से बिलहत की ओर अपने गांव कान्हानगला जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहम्मद उमर और फरमान सड़क किनारे जा गिरे। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को घटपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें बरेली के लिए रेफर कर दिया। आला हजरत हॉस्पिट बरेली ने भी हालत नाजुक देख कर मना कर दिया श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। जिले में तेज रफ्तार और वाहन चालकों की लापरवाही लगातार सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनी हुई है। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके।

मोहम्मद उमर व फरमान पुत्र रजा हुसैन अपनी मोटरसाइकिल संख्या नंबर अप 24V7162 पर बैठकर दिन जुम्मा को दिनावर से अपने गांव घर वापस जा रहा था समय लगभग 9:30 बजे बिनावर बुलेट रोड पर मोड़ से पहले ग्राम रफियाबाद पर था कि सामने विलायत की तरफ से लोडर गाड़ी संख्या अप 24AT1531 पिकअप चालक अपनी गाड़ी बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर आ रहा था मोहम्मद उमर व फरमान की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी मोहम्मद उमर के चारो हाथ पैर टूट गए और पूरे शरीर में खुली व गुम चोट आई है व गुप्तांगों पर खुली चोट आई दोनों घायलों का उपचार श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल बरेली में चल रहा है परिजनों ने थाना बिनावर

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://forms.gle/VEThcFgMcknGFc1u9

TEMPLE OF LIBERALIZATION AND SOCIAL WELFARE ALLIED TRUST REGT.
MEMBERSHIP FORM FOR TOLWA TRUST
transportvisheshcontent@gmail.com Switch account
The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form
* Indicates required question
How you got aware about TOLWA trust *
- [ ] Social Media
- [ ] News Paper
- [ ] Personal connection
- [ ] Youtube
- [ ] Social Function/ RTO/friends/family

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

प्रेम पच्चीसा (भाग 23)उज्जैन नगरी में

पंचायत खत्म होते ही माया और रोहन अपने समाज सेवा केंद्र लोट रहे थे कि रास्ते में हेमंती रोते - रोते बताई उसका पति आनंद अजीवन कारावास से मुक्त होकर घर आया तो रात दिन मेहनत- मजूदरी करके दो साल तक सही था। लेकिन बेटी रिया अब कालेज जाना चाहती है उसकी पढ़ाई - लिखाई का जो पैसा था आनंद जुआ में हार गया है । घर कैसे चलाए और बेटी को आगे पढ़ाएं ? लेख को आगे बढ़ाएं माया और रोहन ने हेमंती की बात सुनकर एक पल के लिए रुक गए। माया, जो खुद एक मजबूत महिला थी और समाज सेवा केंद्र की संचालिका, ने हेमंती के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, ₹हेमंती दीदी, रोना बंद करो। हम हैं ना तुम्हारे साथ। चलो, केंद्र पर चलते हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। सब ठीक हो जाएगा।

रोहन, जो युवा और उत्साही था, ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे तीनों साथ-साथ केंद्र की ओर चल पड़े। केंद्र पहुंचते ही माया ने हेमंती को पानी पिलाया और आराम से बैठने को कहा। हेमंती ने फिर से अपनी कहानी दोहराई – कैसे आनंद की जेल से रिहाई के बाद परिवार में ख़ुशी लौटी थी, कैसे उसने दिन-रात मजदूरी करके घर चलाया, लेकिन जुआ की लत ने सब बर्बाद कर दिया। बेटी रिया अब 18 साल की हो चुकी थी और कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन पैसे का नामोनिशान नहीं था। घर में राशन तक मुश्किल से चल रहा था। रोहन ने ध्यान से सुना और बोला, ₹दीदी, सबसे पहले तो आनंद भैया को जुआ की लत से छुटकारा दिलाना होगा। हमारे केंद्र में एक काउंसलिंग प्रोग्राम है, जहां विशेषज्ञ आते हैं। हम उन्हें वहां ले जा सकते हैं। और रिया की पढ़ाई के लिए, हम सरकारी स्कॉलरशिप के बारे में पता करेंगे। मैं ख़ुद फ़ॉर्म भरने में मदद करूंगा।

माया ने अपनी डायरी निकाली और कुछ नोट्स बनाए। ₹हेमंती, तुम्हारी तरह कई महिलाएं हमारे पास आती हैं। हम एक महिला स्व-सहायता समूह चला रहे हैं, जहां तुम छोटा-मोटा काम करके कमाई कर सकती हो – जैसे सिलाई, अचार बनाना या हैंडीक्राफ्ट। इससे घर चल सकता है। और आनंद के पास तो खेत है उसमें मौसमी साख सब्ज़ी लगाए अगर मज़दूरी का काम चाहिए, तो मैं गांव के ठेकेदार से बात करूंगी। लेकिन वादा करो, तुम हिम्मत नहीं हारोगी।₹ हेमंती की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उम्मीद की चमक भी। उसने कहा, ₹बहन, तुम्हारे जैसे लोग हैं तो दुनिया अभी बाकी है। मैं आनंद से बात करूंगी। कल ही केंद्र पर आऊंगी।

अगले दिन, हेमंती आनंद को लेकर आई। आनंद शर्मिंदा था, उसकी आँखों बह रहे थे लेकिन माया और रोहन की बातों से उसका मन बदलने लगा। काउंसलिंग सेशन शुरू हुआ, और रिया के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन भरा गया। धीरे-धीरे परिवार फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन गांव में एक नई समस्या उभरी – पंचायत के कुछ लोग आनंद के अतीत को लेकर अफवाहें फैला रहे थे, जो परिवार को परेशान कर रही थीं। माया ने सोचा, अब इस मुद्दे को भी सुलझाना होगा...

राजेन्द्र रंजन गायकवाड़
सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक
बिलासपुर,छत्तीसगढ़

उत्तर भारत की भीषण बाढ़: आगरा के समाजसेवियों की भावुक अपील - 'आज मानवता की परीक्षा की घड़ी है'

इसी संकट की घड़ी में, आगरा के समाजसेवियों ने एकजुट होकर समूचे देशवासियों से अपील - 'अब मौन रहने का समय नहीं, मदद के लिए हाथ बढ़ाने का समय है।'

आगरा, संजय साग़र सिंह। उत्तर भारत में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। इसी संकट की घड़ी में, आगरा के समाजसेवियों ने एकजुट होकर समूचे देशवासियों से अपील की है - अब मौन रहने का समय नहीं, मदद के लिए हाथ बढ़ाने का समय है।

'मानव धर्म की असली परीक्षा अब है' - राजेश खुराना

वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने इस आपदा को "मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा" करार देते हुए कहा, ₹हमारे पास जो भी है, उसी में से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए निकालना आज सबसे बड़ा मानव धर्म है।₹ उन्होंने बताया कि किस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं होंगे। ₹आज समय है कि हम एकजुट हों, समाज के हर वर्ग से सहयोग मिले तभी यह संकट पार हो सकेगा।₹

'अब राजनीतिक शब्द नहीं, कर्म बोलेंगे' - अरविन्द पुष्कर

समाजसेवी अरविन्द पुष्कर ने ज़मीनी स्तर पर हो रहे राहत कार्यों की सराहना करते हुए कहा, ₹यह समय केवल राजनीतिक वादों और भाषणों का नहीं है, बल्कि वास्तविक कर्मों का है।₹ उन्होंने जानकारी दी कि विभिन्न स्वयंसेवी संगठन दवाइयां, स्वच्छता किट, भोजन, मच्छरदानी और अन्य आवश्यक सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुँचा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक छोटी सी मदद भी किसी के लिए जीवन रेखा बन सकती है।

'ये वही किसान हैं जो हमें अन्न देते हैं' - कृष्ण मुरारी माहेश्वरी

वरिष्ठ समाजसेवी कृष्ण मुरारी माहेश्वरी ने बाढ़ प्रभावित किसानों की दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए कहा,₹आज जिनके घर बह गए, खेत बर्बाद हो गए, वे वही किसान हैं जो साल भर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए कुछ करें।₹ उन्होंने कहा कि हालात बेहद चिंताजनक हैं - लोग खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को विवश हैं। कई गांवों में घर, सड़कें और पुल बह चुके हैं।

'जब-जब पंजाब पर संकट आया, लोगों ने सेवा का परिचय दिया' - सावन चौहान

समाजसेवी सावन चौहान ने कहा,₹चाहे कोरोना रहा हो या अन्य आपदाएं, पंजाब और उत्तर भारत के लोगों ने हमेशा जुझारूपन और सेवा-भाव से मिसाल कायम की है। आज हमें फिर वही भावना जगानी होगी।₹ उन्होंने उद्योगपतियों, कॉरपोरेट समूहों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे खुलकर सहयोग करें चाहे आर्थिक सहायता हो, राहत सामग्री हो या स्वयं सेवा।

'हमारे पास जो है, वही काफी है – यदि हम बाँटें' - पंकज जैन

समाजसेवी पंकज जैन, जो स्वयं अनेक वर्षों से सेवा कार्यों से जुड़े हैं, ने भावुक स्वर में कहा, ₹हालांकि मैं स्वयं भी कठिनाइयों से जूझ रहा हूँ, लेकिन यह समय दूसरों के लिए खड़े होने का है। सेवा का अर्थ ही है - अपने कष्टों से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करना।₹ उन्होंने बताया कि कई स्वयंसेवी संस्थाएँ अब भी बाढ़ पीड़ितों तक सूखा राशन, पीने का पानी, दवाइयाँ, बच्चों के लिए दूध और बिस्कुट, पशुओं के लिए चारा और तिरपाल पहुँचा रही हैं।

देश को चाहिए एकजुटता, संवेदनशीलता और सहयोग

इन सभी समाजसेवियों की मार्मिक अपील केवल आगरा तक सीमित नहीं - यह एक राष्ट्रीय आह्वान है। संकट की इस घड़ी में आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग से, हर कोने से सहायता की लहर उठे। यह वक्त एकजुटता, सहयोग और संवेदना का है। बाढ़ से तबाह हुए परिवारों को हमारी जरूरत है- आज नहीं तो कब?

आप भी सहयोग कर सकते हैं, आप भी आर्थिक सहायता, राहत सामग्री स्वयंसेवा के माध्यम से इस आपदा में योगदान दे। आप सभी कि हर मदद मायने रखती है - चाहे वह छोटी हो या बड़ी।

रोज दाल में मिला दीजिए ये 5 पत्ते, टनाटन रहेगी सेहत, ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होगा हाई, जानें बेजोड़ फायदे

करी पत्ते में मौजूद पोषक तत्व

करी पत्ते एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो कई तरह की सेहत संबंधित समस्याओं को दूर रखते हैं. इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर, फ्लेवोनॉएड्स, अमीनो एसिड आदि भरपूर होते हैं.

कोलेस्ट्रॉल लेवल रखे कंट्रोल- करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकते हैं. इससे बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं बनता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. इससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है.

पाचन रखे दुरुस्त- करी पत्ता खाने से पाचन तंत्र भी हेल्दी रहता है. करी पत्ता ब्लोटिंग, सूजन, व्यर्थ और टॉक्सिक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है.

लिवर के लिए है हेल्दी- करी पत्ते में मौजूद टैनिन कम्पाउंड, विटामिन ए, सी सभी टॉक्सिक पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं. एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे लिवर की कार्य क्षमता सही रहती है. लिवर स्वस्थ रहता है.

बालों का ग्रोथ हो सही से- आपके बाल झड़ते हैं, रूसी हो गई है, स्कैल्प पर इंचिंग, फोड़े-फुंसी होते रहते हैं तो करी पत्ते का सेवन करना चाहिए. इसमें एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं, जो बालों से लेकर स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं. ये बालों को मजबूती देते हैं, इन्हें शाइनी बनाते हैं.

वेट घटाए- करी पत्ते खाने से या करी पत्ता वाला पानी पीने से वजन कम हो सकता है. यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं. शरीर से टॉक्सिन पदार्थों को बाहर निकालता है.

ब्लड सर्कुलेशन सुधारे- इसके रेगलुर सेवन से शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता रहता है.पीरियड्स से रिलेटेड कई समस्या महिलाओं को होती हैं. पेट दर्द, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, इनसे भी राहत दिलाता है

जीवन चरणों में दुख उपाय

प्रथम चरण :-आयु 58 से 65 वर्ष कार्यस्थल आपसे दूर होता जाता है। अपने करियर के दौरान आप चाहे कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों न हों, अब आपको एक साधारण व्यक्ति ही कहा जाएगा। इसलिए, अपनी पिछली नौकरी या व्यवसाय की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें

दूसरा चरण:-आयु 65 से 72 वर्ष इस आयु में, समाज भी धीरे-धीरे आपको दूर कर देता है। आपके मिलने-जुलने वाले दोस्त और सहकर्मी कम हो जाएँगे और आपके पिछले कार्यस्थल पर शायद ही कोई आपको पहचानता हो। यह न कहें कि ₹मैं था...₹ या ₹मैं कभी था...₹ क्योंकि युवा पीढ़ी आपको नहीं पहचानेगी, और आपको इसके बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए !

तीसरा चरण:-आयु 72 से 77 वर्ष इस कैंप में, परिवार धीरे-धीरे आपको दूर कर देगा। भले ही आपके कई बच्चे और नाती-नातिन हों, लेकिन अधिकतर समय आप अपने साथी के साथ या अकेले ही रह रहे होंगे। जब आपके बच्चे कभी-कभार आते हैं, तो यह स्नेह की अभिव्यक्ति है, इसलिए उन्हें कम आने के लिए दोष न दें, क्योंकि वे अपने जीवन में व्यस्त हैं और अंत में 77+ के बाद,

धरती आपको नष्ट करना चाहती है। इस समय, दुखी या शोक मत करो, क्योंकि यह जीवन का अंतिम चरण है, और हर कोई अंततः इसी मार्ग का अनुसरण करेगा !

इसलिए, जब तक हमारा शरीर अभी भी सक्षम है, जीवन को भरपूर जिएँ !

जो पसंद है वो खाएँ,
पीएँ, खेलें और जो पसंद है वो करें।
खुश रहें, खुशी से जिएँ..

प्रिय वरिष्ठ नागरिक भाइयों और बहनों,

58+ के बाद दोस्तों का एक समूह बनाएँ और कभी-कभार एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर मिलते रहें। टेलीफोनिक संपर्क में रहें। पुराने जीवन के अनुभवों को याद करें और एक-दूसरे के साथ साझा करें

!!!सदा प्रसन्न रहें। प्रसन्न हृदय ईश्वर की परम अराधना है जो विरलों को ही प्राप्त होती है !!!

आत्मरक्षा में धर्मयुद्ध करना मनुष्य का परम धर्म है

"संन्यास और सन्यासी"

(१) संन्यास किसे कहते हैं ?
किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना।
(२) संन्यासी कैसा होना चाहिये ?
रागरहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि-असिद्धि में निर्विकार होना चाहिये
(३) संन्यास का साधन कैसा होना चाहिये ?
सात्त्विकी बुद्धिवाला, वैराग्यवान्, एकान्त का सेवन करने वाला, इन्द्रियों का नियमन करनेवाला, शरीर-वाणी-मनको संयत करनेवाला आदि होना चाहिये।
(४) संन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिये ?
कर्तृत्वाभिमान और राग-द्वेष से रहित होकर कर्म करना।
(५) संन्यासी का भाव कैसा होना चाहिये ?
सम्पूर्ण विभक्त प्राणियों में विभागरहित एक परमात्मतत्त्व को देखना।
(श्रीमद्भगवतगीता ,अध्याय १८ ,११०२)

हम सोचते हैं कि हमने तो हमेशा ही प्रेम से जीवन को देखा है और ठीक से देखा तो पता चलता है कि कोई एक भी मेरा नहीं हुआ

रास्ते में सब मिलते चले गये, सोचा उन सबको अपना बना लें, लेकिन हम कितना भी प्रयास करें कोई प्रसन्न नहीं हुआ। हमारे स्निग्ध भाव को देखकर, सभी ने हमें उपयुक्त गुलाम समझ लिया। हमारी निष्प्रयोजन प्रसन्नता में प्रत्येक को कुछ छल प्रतीत हुआ। और जो समाज के छल को जानते थे, उन्होंने अपनी अवसरवादिता के चलते सब प्रकार प्रभाव जमा लिया। और इसी बहाने हमें संसार से उदासीनता/विरक्ति आ गई। शुरू में लोगों/ संबंधों/ सामानों/संपत्तियों से हमने जो मोह जोड़ा था, इस संसार ने अपनी क्षणभंगुरता दिखाकर हमारा भ्रम तोड़ दिया। और अच्छा ही किया जो हमारा भ्रम टूटा। न टूटता तो हम न जाने कब तक/कितने वर्षों/कितने जीवनों तक इसी भ्रम में रहते कि शायद इस संसार में कोई रस होगा। थोड़ा और प्रयास करें, शायद अभी हमें मिलना तय हो। थोड़ा और हाथ-पैर मारते तो शायद मिल ही जाये। लेकिन भ्रम टूटा, इस भ्रम को टूटने/तोड़ने में बहुत-बहुत लोगों/संबंधियों/ परिस्थितियों की अनुकम्पा रही। वह सभी आज हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। यदि कोई भरोसा दिलाये रखता तो न जाने कितने समय तक भटकते रहते। आभार है उन सबका। धन्यवाद है उन सबका, जिनके छोटे से झटके ने हमें 'संसार' की यात्रा से 'आध्यात्म' की यात्रा में पहुंचा दिया। अभी यात्रा में ही हैं। कभी भटक भी जातें हैं तो कोई आकर हमें फिर यथोचित मार्ग पर ले आता है। इस संसार की बहुत बहुत अनुकम्पा है हम पर जिसने हमें बहकने से बचा लिया। जिसने हमारी यात्रा छोटी कर दी अन्यथा हम इसे ही लम्बाये चले जाते और चूक जाते इस जीवन के लक्ष्य से, जिसे हम लेकर आये हैं।

दान का रहस्य

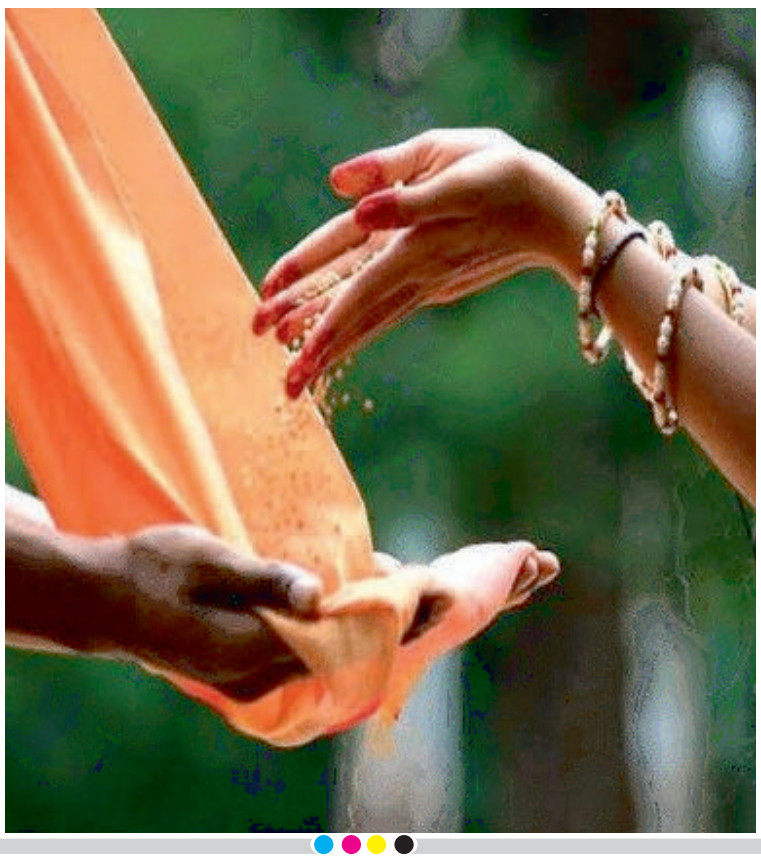

दान में महत्व है त्याग का, वस्तु के मूल्य या संख्या का नहीं | ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्र को यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है, उसे वह वस्तु देना और उसमे किसी प्रकार की कामना न रखना उतम दान है | निष्कामभाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना सात्विक दान है | संत श्रीएकनाथजी की कथा आती है कि एक समय प्रयाग से काँवर पर जल लेकर श्रीरामेशवरम चढाने के लिये जा रहे थे | रास्ते में जब उन्होंने एक जगह देखा कि एक गदाह प्यास के कारण पानी के बिना तड़प रहा है, उसे देखकर उन्हें दया आ गयी और उन्होंने उसे थोड़ा-सा जल पिलाया, इससे उसे कुछ चेत-सा हुआ | फिर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके सब जल उसे पिला दिया | वह गदाह उठकर चला गया | साथियों ने सोचा कि त्रिवेणी का जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गयी | तब एकनाथजी ने हँसकर कहा – 'भाइयो, बार-बार सुनते हो, भगवान् सब प्राणियों के अंदर हैं, फिर भी ऐसे बावलेपन की बात सोचते हो ! मेरी पूजा तो यहीं से श्रीरामेश्वरम को पहुँच गयी | श्रीशंकर जी ने मेरे जल को स्वीकार कर लिया |'

दिल्ली: शाहदरा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध शराब जब्त, तीन आरोपी

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। शाहदरा जिला पुलिस की एएसबी सेल ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5840 क्वार्टर अवैध देसी शराब और एक कार को जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई आगामी त्यौहारी सीजन में कानून व्यवस्था को सुचारू रखने और संगठित अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से की गई।

दरअसल, 6-7 सितंबर की रात शाहदरा एएसबी सेल को सूचना मिली थी कि आनंद विहार इलाके के सूरजमल विहार अथॉरिटी के पास अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के बाद एसआई अजय तोमर, शाहदरा एएसबी सेल के इंचार्ज के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस कार्रवाई की देखरेख एसीपी ऑपरेशन मोहिंदर सिंह ने की, जबकि शाहदरा डीसीपी ने इसकी निगरानी की। टीम में एएसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल सचिन, नवदीप, कुमार दिव्य वत्स, रोहित, सोनू, मनीष और कांस्टेबल सौरव शामिल थे।

इसी दौरान आबकारी विभाग की टीम भी वाहन को ट्रैक कर रही थी। आबकारी इंस्पेक्टर इंदरपाल, हेड कांस्टेबल अमृत और महिला हेड कांस्टेबल नीलम मौके पर पहुंचे और संयुक्त प्रयासों से पुलिस ने आरोपी कमल

(26), निवासी जेलोर वाला बाग, अशोक विहार, दिल्ली को पकड़ लिया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब और वाहन बरामद किया गया। इस संबंध में आनंद विहार थाने में एफआईआर संख्या 407/25 दर्ज की गई है।

पूछताछ में कमल ने कबूल किया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। बेरोजगारी के चलते वह करीब 2-3 महीने पहले वजीरपुर में जॉनी और किशन उर्फ सुदामा से मिला था। उन्होंने उसे 20 हजार मासिक वेतन पर अवैध शराब सप्लाई करने का काम दिया। जॉनी हरियाणा से शराब लाता था और कमल व किशन उर्फ सुदामा के जरिए दिल्ली में सप्लाई कराता था।

पुलिस ने आगे की जांच में किशन कुमार उर्फ सुदामा (24), निवासी बुराड़ी और मूल निवासी मुंगेर, बिहार को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने बताया कि 6 सितम्बर को जॉनी ने 122 कार्टन शराब कुंडली में भेजी थी, जिसे टाटा ऐस में डालकर दिल्ली लाया गया। इस खेप में से 6 कार्टन राजीव उर्फ़ मोनू को शक्ति नगर की गुड़ मंडी में पहुंचाई गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने राजीव उर्फ मोनू (38), निवासी शक्ति नगर, दिल्ली को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 40 क्वार्टर 'रेस 7 – फॉर सेल इन हरियाणा ओनली' शराब बरामद हुई।

छापेमारी के दौरान कुल 5,000 क्वार्टर (100 पेटी) देशी शराब 'संतरा', 440 क्वार्टर (8 पेटी) 'रेस-7', 400 क्वार्टर (8 पेटी) 'नाइट ब्लू' और सप्लाई के लिए उपयोग की जाने वाली कार बरामद की गई।

आरोपी कमल 10वीं तक पढ़ा है और लेबर का काम करता था, लेकिन आसान पैसे कमाने के लालच में शराब तस्करी में शामिल हो गया। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं, किशन कुमार उर्फ सुदामा पहले भी दो बार आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ा जा चुका है। राजीव उर्फ मोनू के खिलाफ पहले से तीन केस दर्ज हैं।

पुलिस ने बताया कि इस मामले का मास्टरमाइंड जॉनी फिलहाल फरार है। हरियाणा के सोनीपत जिले के असावरपुर स्थित उसके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसकी तलाश और बाकी खेप की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। शाहदरा पुलिस ने कहा कि त्योहारों से पहले अवैध शराब और संगठित अपराधों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे।

सब्जी मंडी में चार मंजिला इमारत गिरी, बड़े हादसे से टला संकट

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली, 09 सितंबर। उत्तर दिल्ली के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी बस्ती में मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एक चार मंजिला पुरानी इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। हादसे की आवाज से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सौभाग्य से इमारत खाली होने के कारण कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हालांकि, घटना के बाद बगल की इमारत में फंसे 14 लोगों को दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान कुछ लोगों के हल्के घायल होने की खबर है। कई वाहन मलबे के नीचे दब गए हैं और बचाव अभियान अभी जारी है।

दमकल विभाग की तत्परता से टला बड़ा नुकसान

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार घटना की जानकारी नियंत्रण कक्ष को रात तीन बजकर पांच मिनट पर मिली, जिसके बाद पांच फायर टेंडर और बचावकर्मी तुरंत मौके पर रवाना किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पास की इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली पुलिस, कैट्स एम्बुलेंस सेवा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है।

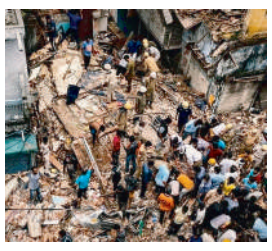

वर्षों पुरानी और जर्जर थी इमारत

जानकारी के अनुसार पंजाबी बस्ती की यह इमारत लगभग 200 गज में बनी थी और वर्षों पुरानी होने के साथ-साथ काफी जर्जर हालत में थी। नगर निगम (एमसीडी) ने इसे पहले ही 'डेंजर' घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद यह ढांचा लंबे समय से जस का तस खड़ा रहा। स्थानीय निवासियों ने कई बार निगम को शिकायत देकर इस बिल्डिंग को गिराने की मांग की थी, पर कार्रवाई नहीं हो पाई। हादसे के बाद लोगों में नाराजगी और चिंता स्पष्ट है।

पास खड़े वाहन मलबे में दबे

इमारत ढहने से आसपास खड़े कई वाहन मलबे के नीचे दब गए। फिलहाल दमकल कर्मी और पुलिस इन्हें निकालने की कोशिश कर रही है। प्रशासन के मुताबिक मलबे की पूरी तरह सफाई तक इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है, ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके।

एमसीडी ने 'डेंजर' घोषित की हुई थी इमारत

सब्जी मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी बस्ती में 200 गज में बनी चार मंजिला एक पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ, उस समय इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, बिल्डिंग के आसपास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही 'डेंजर' यानी खतरनाक घोषित किया हुआ था। इसके बावजूद, यह इमारत कई सालों से ऐसे ही खड़ी थी, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई थी। आसपास के लोगों ने कई बार इस बाबत लिखित शिकायत भी दी थी पर निगम की तरफ से समय रहते बिल्डिंग को नहीं गिराया गया।

एमएएमसी और मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली में मचा हड़कंप

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था मंगलवार सुबह उस समय हिल गई जब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) और मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया कि एमएएमसी में दोपहर 2:45 बजे और मुख्यमंत्री सचिवालय में 3:30 बजे विस्फोट होगा। सूचना मिलते ही पूरे प्रशासनिक तंत्र को अलर्ट कर दिया गया और दोनों स्थानों पर सघन तलाशी अभियान आरंभ कर दिया गया।

धमकी भरे ईमेल से खलबली

सुबह पुलिस नियंत्रण कक्ष को यह ईमेल प्राप्त होते ही दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने मानक संचालन प्रक्रिया के तहत तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) तथा बम डिस्पोजल टीमें मौके पर पहुंचीं और संदिग्ध वस्तुओं की तलाश शुरू की। एमएएमसी के डॉक्टरों, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी प्रशासनिक कार्य सीमित कर दिए गए।

जांच एजेंसियां एक्शन मोड में

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह ईमेल हाल ही में सामने आए कुछ फर्जी धमकी संदेशों से मिलता-जुलता प्रतीत हो रहा है। फिर भी प्रशासन ने कोई जोखिम न उठाते हुए पूर्ण सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय: एडिशनल डीसीपी-1 सेंट्रल, एसीपी कमला मार्केट और एसएचओ आईपी एस्टेट मौके पर मौजूद रहकर तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। एंटी-सबोटाज जांच जारी है। एमएएमसी परिसर: एटीओ आईपी एस्टेट के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने गहन जांच अभियान संचालित किया। साइबर जांच: सेंट्रल जिला साइबर थाना ईमेल की उत्पत्ति और प्रेषक की पहचान में जुटा है। अन्य एजेंसियां: दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल सेल को भी इस अभियान में सम्मिलित किया गया है।

घबराएं नहीं, सतर्क रहें

दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे शांति और संयम बनाए रखें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया, "स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। नागरिकों से अनुरोध है कि अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।"

"सुदेश जी और उनकी बेटी ने फ़न वे लर्निंग एनजीओ के बच्चों को स्टेशनरी बाँटी। धन्यवाद सुदेश जी और आपकी बेटी।"

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा–डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है–
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
• पुराने कपड़े
• पुराने कंबल
• पुराने जूते-चप्पल
• बच्चों के लिए बैग
• किताबें
आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
• दशहरे के दूसरे दिन
• दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
• स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

'नेपाल का ऑनलाइन लॉकडाउन: आज़ादी पर सवाल'

(सोशल मीडिया पर नेपाल का बड़ा ताला: लोगों की आवाज़ पर रोक या नियमों की ज़रूरत?)

नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया और संदेश भेजने वाले मंच—जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पहले ट्विटर) शामिल हैं—को देश में बंद करने का आदेश दिया है। सरकार का तर्क है कि कंपनियों ने स्थानीय कार्यालय नहीं खोला और शिकायत निवारण व्यवस्था नहीं बनाई, जिससे अफवाहें और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। आलोचक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। इस कदम से आम नागरिक, परिवार, व्यापारी और सामग्री निर्माता प्रभावित होंगे। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध की बजाय कंपनियों को नियमों का पालन कराने और जनता की आवाज़ सुरक्षित रखने वाला संतुलित समाधान बेहतर होगा।

– डॉ प्रियंका सौरभ

नेपाल जैसे छोटे लोकतांत्रिक देश ने हाल ही में ऐसा बड़ा निर्णय लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सरकार ने 26 सोशल मीडिया और संदेश मंचों पर अचानक रोक लगाने का आदेश दिया। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सबसे लोकप्रिय मंच शामिल हैं। यह फैसला जितना अचानक लिया गया, उतना ही गहरी बहस भी शुरू कर दी कि क्या यह कदम नागरिक अधिकारों पर हमला है या देश की डिजिटल सुरक्षा के लिए जरूरी था।

सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे नेपाल में अपना स्थानीय कार्यालय खोलें, प्रतिनिधि नियुक्त करें और शिकायत निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया। सरकार के अनुसार, इस कारण अफवाहें, भ्रामक खबरें और साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। इसे रोकने के लिए ही यह बड़ा कदम उठाया गया।

लेकिन इस फैसले का विरोध भी तेजी से हो रहा है। पत्रकार संगठन, मानवाधिकार समूह और आम नागरिक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। उनका तर्क है कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह अब नागरिकों की आवाज़ और लोकतंत्र का आधार बन चुका है। जब इतने बड़े स्तर पर मंच बंद कर दिए जाएंगे, तो जनता की संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा असर पड़ेगा।

नेपाल में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य विदेशों में काम कर रहे हैं। उनके लिए व्हाट्सएप और फेसबुक ही परिवार से जुड़े रहने का सबसे आसान माध्यम हैं। इस प्रतिबंध से उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी कठिन हो जाएगी। यही नहीं, छोटे व्यापारी और ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचते थे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर विज्ञापन देकर वे अपने उत्पाद बेचते थे। अब यह सब प्रभावित होगा।

हजारों सामग्री निर्माता और यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया से अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे थे, अचानक बेरोज़गार होने की कगार पर पहुँच गए हैं। युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि डिजिटल रोजगार पर भी बड़ा झटका है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह निर्णय नेपाल सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विपक्ष इसे तानाशाही कदम मान रहा है। उनका कहना है कि सरकार आलोचना और सवालों से डर रही है, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर रोक लगा दी। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज़ में है। जब उस आवाज़ को दबाया जाता है, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल की छवि प्रभावित होगी। निवेशक और डिजिटल कंपनियाँ यह सोचेंगी कि नेपाल का डिजिटल माहौल स्थिर और सुरक्षित नहीं है। इससे निवेश और साझेदारी पर असर पड़ेगा। पर्यटक भी नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि आज यात्रा, संचार और जानकारी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर आधारित है।

सरकार का तर्क बिल्कुल गलत नहीं है। सोशल मीडिया पर अफवाहें, फर्जी खबरें और साइबर अपराध तेजी से फैल रहे हैं। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा भी भड़क सकती है। सरकार को यह हक़ है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और कंपनियों को जिम्मेदार बनाए। लेकिन समस्या का हल सीधे मंचों को बंद करना नहीं होना चाहिए।

दुनिया के कई देशों ने सोशल मीडिया कंपनियों पर नियम लागू किए हैं। भारत ने 2021 में नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम बनाए, जिनमें कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना और सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करना अनिवार्य किया गया। यूरोपियन संघ ने भी डिजिटल सेवा कानून लागू किया। लेकिन कहीं भी इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। नेपाल का कदम इसलिए कठोर और जल्दबाज़ी भरा लगता है।

समाधान यही है कि सरकार कंपनियों से बातचीत करे, उन पर जुर्माना लगाए और नियमों का पालन करने के लिए दबाव बनाए। जनता की आवाज़ को पूरी तरह रोकना सही तरीका नहीं है। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि जनता और सरकार के बीच अविश्वास भी बढ़ाएगा।

भविष्य में नेपाल को संतुलन की राह चुननी होगी। उसे समझना होगा कि सोशल मीडिया अब केवल तकनीकी साधन नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसे बंद करना लोगों की स्वतंत्रता और संवाद दोनों पर चोट है। बेहतर होगा कि सरकार कंपनियों को सख्त नियमों के दायरे में रखे, लेकिन नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित भी रहे।

लोकतंत्र की असली ताकत जनता का भरोसा है। यह भरोसा तभी बनता है जब सरकार जनता से संवाद करेगी, न कि उसकी आवाज़ को दबाएगी। नेपाल को चाहिए कि वह अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और ऐसा रास्ता अपनाए जिससे कानून का पालन भी हो और नागरिकों की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। यही सही लोकतांत्रिक समाधान है।

नेपाल की यह घटना पूरे विश्व के लिए भी सीख है। यह दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में नियमों और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। एक ओर सुरक्षा, अफवाहों और अपराधों पर नियंत्रण की जरूरत है, तो दूसरी ओर जनता की अभिव्यक्ति और संवाद की स्वतंत्रता का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। यदि यही संतुलन मिल जाता है, तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा और डिजिटल दुनिया का लाभ सभी को मिलेगा।

नेपाल के निर्णय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारें डिजिटल दुनिया में सही कदम उठाने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी का मतलब जनता की आवाज़ पर अंकुश लगाना नहीं होना चाहिए। हर लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। इसलिए नेपाल को चाहिए कि वह कानून की कठोरता और लोगों की स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाए और सोशल मीडिया को केवल प्रतिबंध का शिकार न बनने दे।

अंततः यह निर्णय एक चेतावनी भी है कि सोशल मीडिया का महत्व अब केवल मनोरंजन या सूचना तक सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र, रोजगार, सामाजिक संवाद और वैश्विक पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। इसे सही ढंग से नियंत्रित करना, नियम लागू करना और नागरिकों की आवाज़ सुरक्षित रखना ही भविष्य की दिशा है।

नेपाल को चाहिए कि वह इस निर्णय का पुनर्विचार करे और ऐसा समाधान निकाले जो कानून का पालन सुनिश्चित करे, अफवाहों और साइबर अपराध पर रोक लगाए, और साथ ही जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखे। यही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है।

उपराष्ट्रपति चनाव: रणनीति में 'इंडिया' के मकाबले एनडीए ने बाजी मारी

परिवहन विशेष न्यूज

संसद भवन में 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्र पति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने शानदार जीत दर्ज की। राज्यसभा के महासचिव एवं निर्वाचन अधिकारी पी.सी. मोदी ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। चुनाव परिणाम ने एक बार फिर संसद में एनडीए की संख्या बल को साबित कर दिया। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 मतों से हराया।

इंडिया गठबंधनः लोकसभा में 235 व राज्यसभा में 84 सदस्य हैं यानी कुल 319 सदस्यों के बावजूद महज 300 वोट मिले।

एनडीए गठबंधनः लोकसभा में 294, राज्यसभा में 128 यानी कुल 422 सदस्य हैं लेकिन 452 वोट मिले। इससे साफ है कि विपक्ष के कुछ वोट इधर-उधर हुए, वहीं एनडीए को अतिरिक्त समर्थन भी मिला।

निर्वाचक मंडल में लोकसभा व राज्यसभा मिलाकर कुल 788 सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन रिक्तियों के चलते संख्या 781 रही। बीजू जनता दल (बीजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मतदान से दूरी बनाई।

उप-राष्ट्र पति पद के चुनाव का

कारण मौजूदा उपराष्ट्र पति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा रहा। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दो वर्ष शेष रहते ही पद छोड़ दिया। राष्ट्र पति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। राजनीति और प्रशासनिक अनुभव के धनी सी.पी. राधाकृष्णन से उम्मीद की जा रही है कि वे संसद की मर्यादा और संवाद की परंपरा को नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे।

शहीद के सम्मान में आयोजित रक्तदान शिविर में एक महिला सहित 72 युवाओं ने अपने रक्तदान से दी 1965 भारत पाक युद्ध के शहीद को श्रद्धांजलि

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर : जिला मुख्यालय के अंतिम छोर पर बसे वीरों की देवभूमि कहे जाने वाले गांव धारौली की सामाजिक संस्था मां-मातृभूमि सेवा समिति द्वारा 1965 भारत-पाक युद्ध में देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले लांस नायक हवा सिंह लांबा जी धारौली के सम्मान में जिला रेडक्रॉस सोसायटी, झज्जर के सहयोग से शहीद हवा सिंह लांबा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धारौली में आयोजित दसवां रक्तदान शिविर में जिला झज्जर के मुबारिकपुर गांव की जागरूक महिला दीपा सहित 72 युवाओं ने रक्तदान किया ।

जहांगीरपुर गांव, जिला झज्जर के डॉ. संदीप गुलिया 26वी बार रक्तदान, कोसली के गोसेवक कमलजीत 26वी बार रक्तदान, अश्वनी मल्हान बाबेपुर गिरधरपुर गांव ने 25वी बार रक्तदान, कोसली मे शिक्षक मास्टर धर्मवीर नाहरवाल, छप्पार निवासी 24वीं बार रक्तदान, मास्टर रोहित यादव, प्रो.लेवी डिस्पोजल हाउस, कोसली ने 19वीं बार रक्तदान, जहाजगढ़ गांव के प्रमोद जांगडा ने 18वीं बार रक्तदान, हरियाणवी लोक गायक अजीत कुमार रगीला ने 18वीं बार रक्तदान, अम्बोली गांव के संजय जाखड़ ने 16वी बार रक्तदान और सुधराना गांव जिला रेवाड़ी के नीरज कुमार ने 16वी बार रक्तदान किया।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी, झज्जर से दीपक कुमार की टीम

मोजूद रही।

रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि रक्तदानी नितेश भौरिया, प्रो. अर्बन युवा रेडीमेड स्टोर, कोसली ने 43वी बार रक्तदान करके किया।

शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार का दायित्व भी बेखुबी निभा रहे 21वी बार के रक्तदानी मास्टर हरबीर मल्हान गिरधरपुर निवासी, कोसली के 18वी बार रक्तदानी व शिक्षाविद मास्टर प्रवीण कुमार यादव व 11वी बार के रक्तदानी व शिक्षाविद मास्टर पवन कुमार, गांव धनीरवास निवासी आदि ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की।

समाजसेवी, शिक्षाविद व 21वी बार के रक्तदानी सुखबीर जाखड़, चेयरमैन, रिलायंस ग्रुप आफ स्कूल्स ने रक्तदान शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

22वी बार रक्तदान कर चुके युद्धवीर सिंह लांबा, अध्यक्ष, मां-मातृभूमि सेवा समिति, वीरों की देवभूमि धारौली ने बताया कि 1. सुखबीर जाखड़, चेयरमैन, रिलायंस ग्रुप आफ स्कूल्स, 2. मंजीत सिंह, प्रो. श्री हँस बैग हाउस, कोसली, 3. मास्टर हरबीर मल्हान गिरधरपुर बाबेपुर निवासी, 4.सोनू कुमार, प्रो. सोनू मोटर वाइंडिंग सेंटर, नहाड रोड कोसली 5.कोसली के कमला मेडिकल स्टोर के प्रो. विक्रम यादव, 6. सीनियर एडवोकेट राकेश लांबा, सिविल कोर्ट, कोसली 7.रक्तदानी मास्टर रोहित यादव कोसली, 8.भाकली के रक्तदानी मास्टर सतीश यादव 9. मास्टर पवन कुमार, गांव धनीरवास 10. मास्टर अशोक कुमार मुबारिकपुर गांव 11. कोसली के समाजसेवी सागर यादव आदि की तरफ से रक्तदान शिविर में विशेष सहयोग रहा ।

पर्यावरण संरक्षण को समर्पित मंजीत सिंह प्रो.श्री हंस बैग व स्टेशनरी हाउस, नत्थू राम काम्प्लेक्स, कोसली ने पहले 50 रक्तदाताओं को एक -एक सॉन्ग ऑफ इंडिया के पौधे उपहार में निशुल्क भेंट स्वरूप दिया।

अरब सागर और हिन्द महासागर के बादलों की भिड़ंत

जयसिंह रावत

जलवायु परिवर्तन और ऋतुचक्र में गड़बड़ी के कितने भयावह परिणाम निकल सकते हैं, इसका उदाहरण इस साल का मानसून है जो सितम्बर में भी डरा रहा है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में रिकार्ड तोड़ वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। अगस्त में लद्दाख में सामान्य से 930 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई जबकि उत्तर भारत में औसत वर्षा 1200 प्रतिशत तक बढ़ी। इन आपदाओं में 100 से अधिक लोग मारे गए, अनेक लापता हैं। उत्तराखण्ड से जम्मू-कश्मीर तक तो तबाही हुई ही, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में भी आपदा का दृश्य है। इसका मुख्य कारण अरब सागर से चलने वाले पश्चिमी विक्षोभ और हिन्द महासागर से आने वाले मानसून की टक्कर मानी जा रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में ये स्थितियाँ और बढ़ेंगी जिससे आपदा प्रबंधन के लिए नयी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।

वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि इस जलप्रलय का कारण पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं की भिड़ंत है। सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में सक्रिय रहते हैं, किंतु जलवायु परिवर्तन ने उन्हें मानसून ऋतु में भी सक्रिय कर दिया है। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न निम्न दबाव प्रणालियाँ हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा के साथ पूर्व की ओर बढ़ती हैं और शीतकाल में वर्षा कराती हैं। मानसून काल में सामान्यतः यह जेट धारा उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिससे विक्षोभ सीमित रहते हैं किंतु 2025 में स्थिति उलट गई। मौसम विभाग के अनुसार जून से अगस्त तक कुल 15 पश्चिमी विक्षोभ दर्ज हुए जबकि सामान्यतः इनकी संख्या दो से अधिक नहीं होती। यह असामान्य वृद्धि जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है।

मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाएं लाता है और निम्न दबाव की रेखा बनाता है। जब पश्चिमी विक्षोभ इससे टकराते हैं तो वायुमंडल में नमी का तीव्र संघनन होता है, परिणामस्वरूप अचानक भारी वर्षा, बादल फटना और त्वरित बाढ़ आती है। अगस्त 2025 में लद्दाख की अतिरिक्त वर्षा तथा उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटना इसी संनादन का प्रत्यक्ष परिणाम था। हिमालय की ऊँचाई इस प्रक्रिया को और प्रबल करती है। मौसम विभाग ने 28 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में इस टक्कर को उत्तर भारत की भीषण बाढ़ का प्रमुख कारण बताया।

विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्कटिक और पश्चिमी एशिया की असामान्य ऊष्मा ने उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा को अस्थिर कर दिया है, जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ मानसून महीनों तक सक्रिय

बने रहते हैं। रीडिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किरण हंट के अनुसार 2025 में पश्चिमी विक्षोभ सामान्य से कहीं अधिक थे, जो ''मानसूनी पश्चिमी विक्षोभ'' की प्रवृत्ति का संकेत है। आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर रघु मुर्तुगुद्दे मानते हैं कि ये प्रणालियाँ पश्चिम एशिया की ऊष्मा वृद्धि से प्रेरित हैं।

जलवायु परिवर्तन से वायुमंडल की नमी धारण क्षमता भी बढ़ी है। क्लॉसियस-क्लैपेरोन समीकरण के अनुसार, तापमान में प्रत्येक एक डिग्री वृद्धि से नमी लगभग सात प्रतिशत बढ़ जाती है। यही अतिरिक्त नमी पश्चिमी विक्षोभ-मानसून टक्कर को और अधिक घातक बना रही है। आर्कटिक ऊष्मा से ध्रुवीय जेट धारा अधिक लहरदार हो गई है, जो उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा को प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप, सर्दियों में विक्षोभ घट रहे हैं और मानसून में बढ़ रहे हैं। हिमालय में हिमनद पिघलने से झीलों का आकार 40 प्रतिशत तक बढ़ चुका है, जिससे हिमनदीय झील फटने का खतरा कई गुना बढ़ गया है।

वैज्ञानिक अध्ययनों ने 15 पश्चिमी विक्षोभों को जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। मौसम और जलवायु गतिशीलता (2024) में 70 वर्षों के आँकड़ों से पश्चिमी विक्षोभ के मौसमी बदलाव की पुष्टि हुई थी। नेचर पत्रिका ने हिमालयी मानसून की अवधि में हुए बदलाव को ताप वृद्धि से जोड़ा और अमेरिकी भूभौतिकी संघ की रिपोर्ट ने पश्चिमी विक्षोभ की बढ़ती तीव्रता का संबंध जलवायु परिवर्तन से स्थापित किया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने भी इस पर विस्तृत समीक्षा दी। वैश्विक मॉडल (सीएमआईपी-6) अनुमान लगाते हैं कि ताप वृद्धि से मानसूनी वर्षा 5.3 प्रतिशत प्रति केल्विन बढ़ेगी।

पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की टक्कर नई नहीं है पर इसकी आवृत्ति व तीव्रता हाल के दशकों में कई गुना बढ़ी है। जून 2013 की केदारनाथ आपदा इसी टकराव से हुई, जब 400 प्रतिशत अतिरिक्त वर्षा ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। जुलाई 2023 में हिमाचल-उत्तराखंड में ऐसे ही संनादन से 223 मिमी वर्षा दर्ज हुई। आँकड़ों से स्पष्ट है कि पहले मानसून में विक्षोभ बहुत दुर्लभ होते थे किंतु 2000 के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 की घटनाएँ इस प्रवृत्ति का चरम उदाहरण हैं।

आईपीसीसी और डब्ल्यूएमओ की रिपोर्टों के अनुसार स-2100 तक भारत में मानसूनी वर्षा लगभग 20 प्रतिशत बढ़ सकती है किंतु यह वृद्धि अत्यधिक अनियमित होगी। हिमालयी क्षेत्र में चरम वर्षा सूचकांक दोगुना हो सकता है और हिमनदीय झील फटने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। कुछ मॉडल अनुमान लगाते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की संख्या घट सकती है, लेकिन उनकी तीव्रता विशेष रूप से मानसून काल में बढ़ेगी। डब्ल्यूएमओ ने अनुमान व्यक्त किया है कि 2025-2029 के बीच 1.5 डिग्री ताप वृद्धि पार होने की 70 प्रतिशत संभावना है, जिससे हिमालयी आपदाएँ और भयावह होंगी। हिमालय, जिसे एशिया का ''जल-स्तंभ'' कहा जाता है, तेजी से संकटग्रस्त हो रहा है। हिमनदों के पिघलने से 2 अरब से अधिक लोगों की जल आपूर्ति, कृषि और आजीविका प्रभावित होगी। अनियमित पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का मिलन बाढ़ और सूखे दोनों परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा जैसा 2025 में देखा गया।

इस संकट से निपटने के लिए ठोस कदम आवश्यक हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान, हिमनदीय झील फटने की निगरानी, बाढ़ अवरोधक संरचनाएँ, वन संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और पेरिस समझौते का पालन जरूरी है। साथ ही हिमालय में अवैध निर्माण व खनन पर सख्त रोक, स्थानीय समुदायों की सहभागिता तथा विश्व वन्यजीव कोष की हिमनद संरक्षण परियोजनाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

रूस का लाइलाज़ बिमारी कैंसर को वैक्सिन से हराने की क्रांतिकारी खोज़ - 'नई वैक्सीन', 'नया इलाज', 'क्रांतिकारी शोध'- "इंटरोमिक्स" कैंसर वैक्सीन

एक नई उम्मीद इंटरोमिक्स" कैंसर वैक्सीन:- वैश्विक शोध जगत में इस खोज को एक संभावित गेम-चेंजर माना जा रहा है। दुनियाँ में विज्ञान पर सबसे बड़ी चुनौती,लाइलाज कैंसर को मात मिलेगी, "इंटरोमिक्स" कैंसर वैक्सीन शीघ्र बाजार में- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

विश्व स्वास्थ्य जगत में कैंसर एक ऐसा सार्वभौमिक संकट रहा है जिसने अनेक बार वैज्ञानिकों को अचम्भित किया है। बढ़ते कैंसर के मामलों और उसके आर्थिक व सामाजिक प्रभावों की चुनौतियों ने एक से अधिक बार चिकित्सा अनुसंधान को अग्रसर किया है।कैंसर आज के समय में इंसानों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, पहले यह बड़े उम्र के लोगों में ज्यादा होता था,लेकिन आज कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में हैं, मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो स्त्री से लेकर पुरुष तक हर कोई कैंसर से परेशान है,इसके अलावा इसके इलाज में काफी खर्च आता है जो आम इंसान कभी-कभी उतना दे नहीं पाता और इसके चलते हर साल बड़ी संख्या में इससे लोगों की मौत हो जाती है, अब इसी बीमारी को काउंटर करने के लिए रूस ने वैक्सीन का निर्माण किया है,यह वैक्सीन अगर इंसानों पर पूरी तरह सफल होती है, तो यह मानव सभ्यता के सबसे महान खोजों में से एक होने वाली है, 8 सितंबर 25 को देर रात्रि आई जानकारी के अनुसार,अभी तक एम-आरएनए बेस्ड वैक्सीन 'एंटरोमिक्स' ने प्री-क्लिनिकल ट्रायल्स में 100 प्रतिशत तक प्रभावशील और सुरक्षित दिखी है, इस वैक्सीन को रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर और रूस के ही एकेडमी ऑफ साइंस के एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार किया है।समाचारों में अक्सरऋनई वैक्सीनऋ,ऋनया इलाजऋ ऋक्रांतिकारी शोधऋ जैसी बातें सामने आती हैं परंतु सच्चाई अक्सर संतोषजनक नहीं होती। इसलिए रूस की वैज्ञानिक टीम द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट, जिसमें दावा है कि "इंटरोमिक्स" नामक एम-आरएनए कैंसर वैक्सीन ग्लोबली प्रीक्लिनिकल से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स में 100 पर्सेंट सफल रही है,वास्तव में एक व्यापक और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन मांगती है।चूँकि एक नई उम्मीद ऋइंटरोमिक्स" कैंसर वैक्सीनः- कैंसर को वैक्सीन से हराने की पहल, वैश्विक शोध जगत में इस खोज को एक संभावित गेम-चेंजर माना जा रहा है।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्धजानकारी के सहयोग से इसआर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,कैंसर के इलाज में रूस की क्रांतिकारी खोज-ऋनई वैक्सीनऋ ऋनया इलाजऋ,ऋक्रांतिकारी शोधऋ- "इंटरोमिक्स" कैंसर वैक्सीन।

साथियों बात अगर हम शोध का दायरा और वैक्सीन का निर्माण व ट्रायल के प्रारंभिक नतीजों की करें तो,रूसी नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एवं एंगेल्हार्डट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मोलेक्युलर बायोलॉजी (रूसी विज्ञान अकादमी) द्वारा मिलकर विकसित की गई "इंटरोमिक्स " वैक्सीन का आधार वही एम-आरएनए तकनीक है जो कोविड-19 वैक्सीन में प्रयोग हुई थी। इसकी खासियत है,यह व्यक्तिगत ट्यूमर जीनोमिक प्रोफ़िलिंग पर आधारित,पूर्णतया कस्टमाइज़्ड थेरेपी है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मरीज के ट्यूमर की जीन-म्युटेशनल विश्लेषण के आधार पर वैक्सीन तैयार की जाती है ताकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें लक्ष्य कर सके। यह प्रयास केवल वर्गगत प्रतिरक्षा (स्टैंडर्ड कैंसर वैक्सीन) से हटकर, सटीक, तेज और प्रभावी चिकित्सा का नेतृत्व करता है। ट्रायल के प्रारंभिक नतीजे--फेज-1 क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें लगभग 48 स्वैच्छिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया था,में मरीजों में ट्यूमर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई और कोई गंभीर साइड-इफेक्ट्स नहीं दर्ज हुए। यह दुर्लभ उपलब्धि

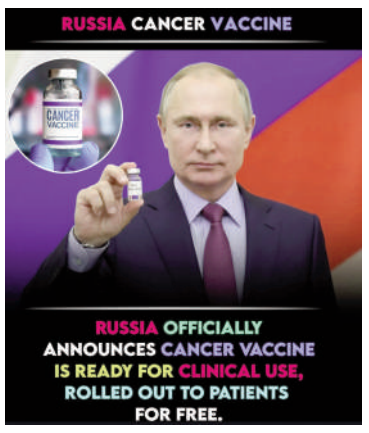

है, क्योंकि कैंसर उपचार में अक्सर कष्टप्रद स्वास्थ्य प्रभाव आते हैं,विशेषकर कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी में। ट्रायल में प्राप्त परिणामों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन सुरक्षित और अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है।

साथियों बात अगर हम कोलोरेक्टल कैंसर पर पहली सफलता व दावे और दूसरी परीक्षण पोकियाँ की करें तो हम देखेंगे कि इंटरोमिक्स की पहली लक्षित उपयोगिता कोलोरेक्टल कैंसर (बड़ी आंत का कैंसर) पर केंद्रित रही। इस कैंसर का वैश्विक स्तर पर प्रसार और मृत्यु दर काफ़ी उच्च है।प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार,इंटरोमिक्स ने कोलोरेक्टल कैंसर से ग्रसित रोगियों में ट्यूमर सिकुड़ने और वृद्धि में बाधा डालने में सफलता हासिल की है।दावे और दूसरी परीक्षण पोकियाँ-रूसी एजेंसी एफएमबीए (फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी) ने घोषणा की है कि कई वर्षों की अनुसंधान अवधि और कम से कम तीन साल के अनिवार्य प्रीक्लिनिकल अध्ययनों के बाद अब यह वैक्सीन ऋउपयोग के लिए तैयारऋ

है,लेकिन "आधिकारिक अप्रूवल" अभी अग्रसर है।रिपोर्ट अनुसार, ट्यूमर की वृद्धि दर में 60 पर्सेंट से 80 पर्सेंट तक की गिरावट दिखाई गई और जीवनकाल में सुधार भी हुआ।

साथियों बात अगर हम अगली चुनौतियोंः ग्लोबल ज़रूरतों और अवरोधों पर नजर डालकर समझने की करें तो, वैश्विक शोध जगत में इस खोज को एक संभावित गेम-चेंजर माना जा रहा है। अगर अगले चरण के ट्रायल—फेज-2, फेज-3,में यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है, तो यह कैंसर उपचार के आसपास के परिदृश्य को बदलने का दम रखती है। हालांकि, वैज्ञानिक विश्व में सामान्यतः ऋफेज-1 की सफलताऋ अंतिम मंज़िल नहीं होती। फेज-2 और फेज-3 के बड़े, व्यापक ट्रायल्स, दीर्घकालिक प्रभाव, उत्पादन-लागत, वितरण व्यवस्था और नियामकीय मंजूरी जैसीचुनौतियाँ अभी बाकी हैं।फिर भी, आज 8 सितंबर 2025 की तारीख में, वैश्विक स्वास्थ्य और कैंसर अनुसंधान की दुनिया में रूस की यह खोज निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय और प्रेरणादायी

मोड़ बन चुकी है, जो नई उम्मीदों को जन्म देती है।यह व्यक्तिगत, मुँहतोड़ और साइड- इफेक्ट-रहित चिकित्सा का भविष्य का प्रवाह हो सकता है।भारत जैसे देशों में, जहाँ कैंसर की बीमारी आर्थिक बोझ और चिकित्सा पहुँच की चुनौतियों के बीच एक गंभीर समस्या है, ऐसी सफलता आशा की किरण बन सकती है,बशर्ते लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर और नियामक अवरोधों का समाधान हो सके।भारत में कैंसर के इलाज पर अनुमानतः 29,000 करोड़ रूपए सालाना खर्च होता है, जिससे अनेक परिवार आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित होते हैं।बच्चों, वृद्धों और समाज पर प्रभाव-कैंसर कोई उम्र-विशिष्ट बीमारी नहीं है,यह बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक किसी को भी प्रभावित कर सकता है। कई बार इस बीमारी से युवा जीवन की संभावना छिन जाती है, या जो लोग बच जाते हैं, उन्हें सारा जीवन आर्थिक और मानसिक संघर्ष करना पड़ता है। अगर इंटरोमिक्स जैसी वैक्सीन हर उम्र वर्ग में सफल हो जाती है, तो यह मानवीय विकास का सबसे महान योगदानों में से एक बन सकती है।

साथियों बात अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्यः इतिहास में सामने आई अन्य कोशिशें तथा डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों की करें तो,पहले भी कुछ देशों और संस्थानों ने कैंसर वैक्सीन विकास की पहल की,जैसे अमेरिका कीऑनकफज (विटेस्पेन) नामक वैक्सीन, जिसे रूस ने भी अप्रूवल दिया था (2008 में शुरुआती-स्टेज किडनी कैंसर के लिए)। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक स्तरपर यह वैक्सीन व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सकीइसलिए इंटरोमिक्स की सफलता सिर्फ एक वैज्ञानिक अध्याय नहीं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक चुनौती और संभावनाओं का भाग हो सकती है। यदि व्यापक परीक्षणों और वैश्विक मान्यता में यह सफल हो जाती है, तो चिकित्सा जगत की चुनौतियाँ और उपचार दृष्टिकोण दोनों परिवर्तित हो सकते हैं।वैश्विक दृष्टिकोण से,विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 2 करोड़ नए कैंसर के मामलों का सामना विश्व करता है, और करीब 1 करोड़ कैंसर के कारण मर जाते हैं।

अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे किरूस का लाइलाज़ बीमारी कैंसर को वैक्सीन से हराने की क्रांतिकारी खोज़ -ऋनई वैक्सीनऋ,ऋनया इलाजऋ, ऋक्रांतिकारी शोधऋइंटरोमिक्स कैंसर वैक्सीनएक नई उम्मीद ऋइंटरोमिक्स" कैंसर वैक्सीनः- वैश्विक शोध जगत में इस खोज को एक संभावित गेम-चेंजर माना जा रहा है।

वोल्वो की गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती, ₹6.92 लाख तक होंगी सस्ती

भारत सरकार द्वारा GST दरों में बदलाव के बाद Volvo कार इंडिया ने अपनी ICE (पेट्रोल/डीजल) कारों की कीमतों में 6.92 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। कंपनी ने अपनी कारों पर आकर्षक फेस्टिव ऑफर्स भी पेश किए हैं जिसे डबल फेस्टिव डिलाइट का नाम दिया गया है। GST में बदलाव का लाभ ग्राहकों को मिलेगा।

नई दिल्ली। इस बार के फेस्टिव सीजन आने से पहले भारत सरकार ने नई GST दरों की घोषणा की है। नए GST दरों की घोषणा के बाद कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में भारी कटौती कर रही है। अब इस लिस्ट मे Volvo भी शामिल हो गई है। वोल्वो कार इंडिया ने आज अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ICE (पेट्रोल/डीजल) पोर्टफोलियो की कारों की कीमतों में 6.92 लाख रुपये तक की भारी कटौती का एलान किया है। ये नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

Volvo लेकर आई फेस्टिव ऑफर

कंपनी की तरफ से अपनी गाड़ियों की कीमत में कटौती के बाद यह फैसला हाल ही में जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए जीएसटी युक्तिकरण के बाद आया है, जिसे ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। इसी के साथ, Volvo ने अपनी कारों पर आकर्षक फेस्टिव ऑफर्स भी पेश किए हैं, जिससे ग्राहकों को दोहरा लाभ मिल रहा है। कंपनी इसे डबल फेस्टिव डिलाइट का नाम दे रही है।

ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा

नई टैक्स सिस्टम ने ऊंचे टैक्स स्लैब को एक सरल व्यवस्था से बदल दिया है, जिससे Volvo की गाड़ियों को इसका सीधा फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का मौका मिला है। इस कटौती के बाद, वोल्वो की शानदार और सुरक्षित कारों की पूरी ICE रेंज अब पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक कीमतों पर मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वोल्वो के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वे भी कंपनी द्वारा दिए जा रहे विशेष त्योहारी ऑफर्स में शामिल हैं।

कंपनी का क्या कहना है?

Volvo कार इंडिया के प्रबंध निदेशक, ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि एक जिम्मेदार व्यवसाय और स्वीडिश लक्जरी कार निर्माता के रूप में, हमारा लक्ष्य लक्जरी मोबिलिटी को अधिक सुलभ बनाना और अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम ऑफर्स प्रदान करना है। 'डबल फेस्टिव डिलाइट' के हिस्से के रूप में जीएसटी लाभ और विशेष ऑफर्स का यह संयोजन भारत में इस सेगमेंट के विकास में हमारे विश्वास को भी मजबूत करता है। हमें उम्मीद है कि यह त्योहारी सीजन हमारे लिए बहुत सफल रहेगा। Volvo इंडिया 2007 से भारत में मौजूद है और देश भर में 25 डीलरशिप के माध्यम से अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। कंपनी सुरक्षित और टिकाऊ मोबिलिटी के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।

नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़ेलियो ग्रेसी भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

ZELIO E मोबिलिटी ने अपना नया लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर Gracyi लॉन्च किया है जो शहरी यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्कूटर 140 किलोमीटर तक की रेंज और 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस प्रदान करता है। Gracyi तीन वेरिएंट में उपलब्ध है जिनकी कीमत 54000 रुपये से शुरू होती है। इसमें 60/72V BLDC मोटर डिजिटल मीटर एलईडी हेडलैंप और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स हैं।

नई दिल्ली। भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में से एक, ZELIO E मोबिलिटी ने आज अपने पॉपुलर लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, Gracyi का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। शहरी यात्रियों, विशेष रूप से छात्रों, पेशेवरों और गिग वर्कर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह स्कूटर बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार आराम और कई आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। नया Gracyi स्कूटर सिंगल चार्ज में 140 किलोमीटर तक की शानदार रेंज और 180 मिमी का जबरदस्त ग्राउंड क्लीयरेंस प्रदान करता है, जो इसे भारतीय सड़कों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नया ZELIO Gracyi को और किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

ZELIO Gracyi तीन वेरिएंट में लॉन्च

ZELIO ने नए Gracyi को ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इन तीनों में अलग-अलग बैटरी कॉन्फिगरेशन में पेश किया है। इसके साथ ही तीनों वेरिएंट की कीमत में बैटरी और रेंज के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

शहर की राइड्स के लिए बनाए गए इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा है। इसमें एक शक्तिशाली 60/72V BLDC मोटर लगी है, जो एक बार फुल चार्ज होने में केवल 1.5 यूनिट बिजली की खपत करती है। कंपनी का दावा है कि लिथियम-आयन वेरिएंट 4 घंटे में और जेल बैटरी मॉडल 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। कंपनी मोटर कंट्रोलर और फ्रेम पर 2 साल की वारंटी, लिथियम-आयन बैटरी पर 3 साल की वारंटी और जेल बैटरी पर 1 साल की वारंटी दे रही है।

ZELIO Gracyi

बेहतर सुरक्षा के लिए इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। इसके साथ ही हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर भी दिया गया है। स्कूटर में डिजिटल मीटर, एलईडी हेडलैंप, कीलेस ड्राइव, एंटी-थेफ्ट अलार्म, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और पैसेंजर फुटरिस्ट जैसे कई उपयोगी फीचर्स भी शामिल हैं। इसे व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट-ब्लैक, येलो-ब्लू और ब्लैक-रेड जैसे पांच कलर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है।

जीप की गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती, ₹4.84 लाख तक होंगी सस्ती

भारत सरकार द्वारा GST दरों में सुधार के बाद Jeep ने अपनी SUV लाइनअप की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। 22 सितंबर 2025 से Jeep Compass की कीमत 2.16 लाख रुपये तक और Jeep Meridian का दाम 4.84 लाख रुपये तक कम हो सकता है। Grand Cherokee Jeep की कीमत में 4.50 लाख रुपये तक की कटोती की जा सकती है

नई दिल्ली। भारत सरकार ने हाल ही में GST की दरों में सुधार किया है। इन GST की दरों में सुधार के बाद कार निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कटौती की है। अब इस लिस्ट में Jeep भी शामिल हो गई है। कंपनी ने GST की दरों में सुधार के बाद अपनी एसयूवी लाइनअप में कीमतों में बड़ी कटौती की घोषणा की है। संशोधित टैक्स ढांचे का पूरा लाभ ग्राहकों को देकर, जीप अपने वाहनों को पहले से कहीं ज्यादा किफायती बना रही है। 22 सितंबर, 2025 से, जीप कंपास (Jeep Compass), मेरिडियन (Meridian), रैंगलर (Wrangler) और ग्रैंड चेरोकी (Grand Cherokee) की एक्स-शोरूम कीमतों में मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमत में कमी होगी।

Jeep की गाड़ियों की कीमत इनती होगी कम

- GST दरों में यह बदलाव पूरे भारत में 22 सितंबर, 2025 से सभी जीप डीलरशिप पर लागू होगा। इस कदम से जीप न केवल अपने ग्राहकों के लिए एसयूवी को ज़्यादा सुलभ बना रही है, बल्कि त्योहारी सीज़न से पहले भी खुद को मजबूती से स्थापित कर रही है।
- GST दरों में बदलाव की वजह से Jeep Compass की कीमत 2.16 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती है। इसके साथ ही Jeep Meridian का दाम 4.84 लाख रुपये तक कम हो सकता है। इसके अलावा, Grand Cherokee Jeep की कीमत में 4.50 लाख रुपये तक की कटोती की जा सकती है।
- ये फायदा, गाड़ी के मॉडल की अधिकतम कीमत पर प्रस्तावित जीएसटी दरों के आधार पर सांकेतिक हैं। वास्तविक बचत वेरिएंट के आधार पर भिन्न हो सकती है।

कंपनी ने क्या कहा?

स्टेलंटिस इंडिया के बिजनेस हेड और निदेशक कुमार प्रियेश ने कहा कि जीएसटी सुधार एक परिवर्तनकारी कदम है जो ग्राहकों के लिए स्पष्टता और सामर्थ्य लाता है। हमें अपने खरीदारों को इसका पूरा लाभ देकर खुशी हो रही है, जिससे जीप लाइफस्टाइल पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई है।

कावासाकी की इस पावरफुल बाइक पर लाखों की छूट, कई पावर मोड और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स से है लैस

कावासाकी बाइक्स पर डिस्काउंट ऑफर

कावासाकी इंडिया ने Versys लाइनअप पर कैशबैक ऑफर की घोषणा की है जिसमें Versys X-300 Versys 650 और Versys 1100 शामिल हैं। यह ऑफर सितंबर के अंत तक या डीलरशिप पर उपलब्धता तक सीमित है। Kawasaki Versys रेंज पर मॉडल के आधार पर 20 हजार से लेकर 1.1 लाख रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है।

नई दिल्ली। कावासाकी इंडिया ने पॉपुलर मोटरसाइकिल Ninja ZX-10R और Ninja 1100SX पर डिस्काउंट के बाद अपनी Versys लाइनअप पर भी बेहतरीन कैशबैक ऑफर की घोषणा की है। इस लाइनअप में Versys X-300, Versys 650 और Versys 1100 शामिल हैं। इस ऑफर को सितंबर के आखिरी तक और डीलरशिप पर उपलब्धता पर निर्भर करता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इन कावासाकी की इन मोटरसाइकिलों पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Kawasaki Versys रेंज पर ऑफर

- कावासाकी Versys रेंज पर मॉडल के आधार पर 20 हजार रुपये से लेकर 1.1 लाख रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है।
- Kawasaki Versys 1100: यह कावासाकी की फ्लैगशिप एडवेंचर टूरर बाइक है, जिसकी कीमत 12.90 लाख रुपये से शुरू होती है। अब इसपर 1.10 लाख रुपये का भारी कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। यह टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, कई पावर मोड और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स से लैस है। 2025 के लिए, इसे 1,099cc का इनलाइन-फोर इंजन मिला है जो 135hp और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- Kawasaki Versys 650: यह कावासाकी की सबसे पॉपुलर बाइक में से एक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.93 लाख रुपये है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत पर 20,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इसमें इसमें 649cc का पैरेलल-ट्विन मोटर लगा है, जो 67hp की पावर और 61Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- Kawasaki Versys X-300: यह कंपनी की एंट्री-लेवल बाइक ही, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.80 लाख रुपये है। इस पर 25,000 रुपये का कैशबैक मिलता है। X-300 में 296cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 40hp की पावर और 26Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- कावासाकी की अन्य बड़ी मोटरसाइकिल की तरह, 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों के लिए सरकार के हालिया जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण - 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक - Versys 650 और Versys 1100 की कीमतों में महीने के अंत तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, 350cc से कम वाली Versys X-300 को नए टैक्स ढांचे के लागू होने पर कीमत में कमी का फायदा मिल सकता है।
- कावासाकी की अन्य बड़ी मोटरसाइकिल की तरह, 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों के लिए सरकार के हालिया जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण - 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक - Versys 650 और Versys 1100 की कीमतों में महीने के अंत तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, 350cc से कम वाली Versys X-300 को नए टैक्स ढांचे के लागू होने पर कीमत में कमी का फायदा मिल सकता है।

नई GST दर का असर: Volvo की गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती, ₹6.92 लाख तक होंगी सस्ती

स्कोडा जीएसटी जीएसटी की दरों में बदलाव की घोषणा के बाद से वाहन निर्माताओं की ओर से भी कारों की कीमत में कमी की जा रही है। स्कोडा की ओर से भी हाल में ही बताया गया है कि वह भी अपनी कारों की कीमत को कम कर रही है। निर्माता किस कार की कीमत को कितना कम कर रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी कारों की कीमत में बदलाव किया जा रहा है। कई वाहन निर्माताओं के साथ ही Skoda की ओर से भी अपनी कारों की कीमत को नई जीएसटी की दरों के मुताबिक अपडेट कर दिया है। साथ ही निर्माता की ओर से और भी फायदों को अपनी कारों के साथ दिया जा रहा है। किस कार पर कितना फायदा मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

स्कोडा ने की घोषणा

वाहन निर्माता स्कोडा की ओर से भी अपनी कारों की कीमत को कम करने की घोषणा कर दी है। हालांकि इन फायदों को सीमित समय के लिए ऑफर किया जा रहा है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से लेकर मिड साइज सेडान कार और फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है।

किस गाड़ी की कीमत में कितनी कमी

स्कोडा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक Skoda Kushaq की कीमत में 66 हजार रुपये तक कम कर दिए गए हैं। Skoda Slavia की कीमत में भी 63 हजार रुपये तक कम किए गए हैं। सबसे ज्यादा कमी निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली Skoda Kodiaq की कीमतों में की गई है। इस कार को अब खरीदना 3.3 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है।

मिल रहा अतिरिक्त फायदा

निर्माता की ओर से अपनी कारों पर जीएसटी में कमी के साथ ही अतिरिक्त फायदे भी दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्कोडा कुशाक पर 2.5 लाख रुपये, स्कोडा स्लाविया पर 1.2 लाख रुपये और स्कोडा कोडिएक पर भी 2.5 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं।

कब तक मिलेगा फायदा

स्कोडा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त फायदे को सीमित अवधि के लिए ऑफर किया गया है। अपनी कारों पर निर्माता की ओर से 21 सितंबर तक ही अतिरिक्त फायदे दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि निर्माता की ओर से इस तरह के ऑफर को अपनी सबसे सस्ती एसयूवी Skoda Kushaq पर नहीं दिया है।

होंडा देगा ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा फायदा, कारें की ₹95,500 तक सस्ती

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले Honda कार्स इंडिया लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने एलना किया है कि वह हाल ही में लागू हुए नए GST दरों का फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगी। Honda की कारों की नई और घटी हुई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। सबसे खास बात यह है कि जो ग्राहक अभी अपनी कार बुक करते हैं, उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा। उन्हें मौजूदा फेस्टिव ऑफर्स के साथ-साथ आने वाली जीएसटी-आधारित कीमतों में कटौती का भी फायदा मिलेगा। नई कीमतों पर कारों की डिलीवरी नवरात्रि की शुभ अवधि से शुरू होगी।

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने फेस्टिव सीजन से पहले जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। नई कीमतें २२ सितंबर २०२५ से लागू होंगी। होंडा अमेज पर 95500 रुपये तक और होंडा सिटी पर 57500 रुपये तक की बचत होगी। अभी बुकिंग करने वाले ग्राहकों को फेस्टिव ऑफर्स के साथ जीएसटी कटौती का भी फायदा मिलेगा। नवरात्रि से कारों की डिलीवरी शुरू होगी।

किस मॉडल पर कितनी होगी बचत?

Honda ने एक अनुमानित बचत लिस्ट जारी की है, जिससे ग्राहकों को अंदाजा लग सके कि GST सुधार लागू होने के बाद उन्हें कितना फायदा होगा सकता है। वेरिएंट के अनुसार अंतिम कीमतें जल्द ही अधिकृत डीलरशिप द्वारा साझा की जाएंगी। कंपनी की तरफ से शेयर की गई कीमतों के मुताबिक, Honda अमेज 3rd जेन पर 95,500 रुपये तक, Honda अमेज 2nd जेन पर 72,800 रुपये तक, Honda एलिवेट पर 58,400 रुपये तक और Honda सिटी पर 57,500 रुपये तक की बचत होगी।

कंपनी का क्या कहना है?

Honda कार्स इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष (मार्केटिंग और सेल्स) कुणाल बहल ने कहा कि हम सरकार के नए जीएसटी सुधार 2025 का स्वागत करते हैं, जो ऑटो उद्योग के लिए बहुत सही समय पर आया है। यह प्रगतिशील कदम न केवल वाहनों को ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ बनाएगा बल्कि त्योहारी सीजन की मांग को भी मजबूत गति प्रदान करेगा। हम अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अभी बुकिंग करें ताकि शुभ अवधि के दौरान समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके और जीएसटी कटौती तथा मौजूदा त्योहारी ऑफर्स, दोनों का लाभ उठा सकें। यह कदम Honda की त्योहारी सीजन में अपनी बिक्री को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी वर्तमान में भारत में अमेज, एलिवेट और सिटी जैसे लोकप्रिय मॉडल बेचती है, और इस दोहरे लाभ की पेशकश से ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।

मेड इन इंडिया अस्पतालः सस्ती और अभिनव

विजय गर्ग

भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को 'मेड इन इंडिया' अस्पतालों की बढ़ती संख्या द्वारा चिह्नित किया गया है जो सस्ती और अभिनव चिकित्सा देखभाल दोनों प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति सरकारी पहलों, एक संपन्न स्वास्थ्य-तकनीक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और स्वदेशी चिकित्सा उपकरण निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के संयोजन से प्रेरित है। भारत में आज, स्वास्थ्य सेवा का विरोधाभास है। एक ओर, देश फार्मास्यूटिकल्स और टीकों में नवाचार और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। दूसरी ओर, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं काफी हद तक महानगरीय शहरों में केंद्रित हैं। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी टियर II, टियर III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, फिर भी तृतीयक देखभाल - कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों या गुर्दे की विफलता जैसी स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है - अत्यधिक मेट्रो-केंद्रित है। यह शहरी तिरछा लाखों परिवारों को लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए मजबूर करता है, अक्सर वित्तीय लागत को कम करने के लिए, देखभाल का उपयोग करने के लिए। इस असंतुलन का समाधान अधिक महानगरीय ₹सुपर-स्पेशियलिटी₹ द्वीप बनाने में नहीं है, बल्कि मेड इन इंडिया हॉस्पिटल्स के निर्माण में है - पूरी तरह से स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित विश्व स्तरीय अभी तक सस्ती संस्थाएं। यह दृष्टि आकांक्षात्मक नहीं है; यह कार्रवाई योग्य है।

सस्ती हेल्थकेयर और प्रमुख खिलाड़ी ₹मेड इन इंडिया₹ हेल्थकेयर मॉडल के सबसे परिभाषित पहलुओं में से एक सामर्थ्य पर इसका जोर है, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता चिकित्सा उपचार को व्यापक आबादी के लिए सुलभ बनाना है। इस प्रयास में कई अस्पतालों और सरकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा हैः

आर्थिक प्रभाव और हेल्थकेयर इक्विटी

मेड इन इंडिया हॉस्पिटल्स का आर्थिक प्रभाव बहु-गुना है। पहला लाभ सस्ती स्वदेशी उपकरणों की सोर्सिंग करके अस्पतालों के निर्माण की कम पूंजी लागत है। दूसरे, ये अस्पताल परिवारों के लिए भयावह स्वास्थ्य खर्च को रोकते हुए, रोगी व्यय को कम कर सकते हैं। तीसरा, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और रसद में स्थानीय नौकरियां उत्पन्न की जाएंगी। अंत में, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, भारत को आयातक से अस्पतालों और उपकरणों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता में बदल दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हेल्थकेयर इक्विटी गैप को बंद कर देते हैं। टियर III शहर में एक कैंसर रोगी को कीमोथेरेपी के लिए मेट्रो से 500 किमी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेड इन इंडिया हॉस्पिटल्स के साथ, देखभाल उनके दरवाजे पर आती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्लीः एक प्रमुख सरकारी संस्थान के रूप में, ऐआईआईऐएस अत्यधिक रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। यह सरकारी धन प्राप्त करता है, जो निजी अस्पतालों की तुलना में परामर्श शुल्क, नैदानिक परीक्षण और सर्जिकल प्रक्रियाओं को काफी सस्ता बनाता है। एम्स

समय से पहले शिशुओं के लिए स्वदेशी सर्फेक्टेंट विकसित करने जैसे अनुसंधान को भी अग्रणी करता है।

नारायण स्वास्थ्यः डॉ। देवी शेट्टी, एक प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन, नारायण हेल्थ उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल को जनता के लिए सस्ती बनाने के लिए समर्पित है। देश भर के अस्पतालों के नेटवर्क के साथ, यह लागत प्रभावी, उच्च मात्रा वाली स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए एक मॉडल बन गया है।

सरकारी योजनाएंः आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेऐवाई) जैसी पहल महत्वपूर्ण हैं। पीएम-जेऐवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो 120 मिलियन से अधिक कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष $ 500,000 प्रति परिवार का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय को कम करना है जो हर साल लाखों लोगों को गरीबी में धकेल देता है। नवाचार और प्रौद्योगिकी भारतीय अस्पताल और स्वास्थ्य-तकनीक कंपनियां नवाचार में सबसे आगे हैं, रोगी की देखभाल में सुधार, संचालन को सुव्यवस्थित करने और स्वदेशी चिकित्सा समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही हैं।

स्वदेशी चिकित्सा उपकरणः चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में ₹मेड इन इंडिया₹ आंदोलन मजबूत है। भारत सिरिंज और कैनुलस जैसे सरल उपभोग्य सामग्रियों से लेकर वेंटिलेटर, सीटी स्कैनर और सर्जिकल रोबोट जैसे अधिक जटिल उपकरणों तक उपकरणों की बढ़ती रेंज का निर्माण कर रहा है।

एसएसआई-मंत्रः एक उल्लेखनीय उदाहरण पहली बार ₹मेड-इन-इंडिया₹ सर्जिकल रोबोट प्रणाली है, जिसे मेड-टेक स्टार्टअप एसएस इनोवेशन द्वारा विकसित किया गया है, और नई दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान में तैनात किया गया है।

मेडिसिसः भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा उपकरण कंपनियों में से एक, मेडिसिस का देश के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित वेंटिलेटर को विकसित करने का इतिहास है और अब रेडियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी उपकरणों को शामिल करने के लिए अपने विनिर्माण का विस्तार कर रहा है।

डिजिटल स्वास्थ्य और एआईः भारतीय स्वास्थ्य-तकनीकी स्टार्टअप अभिनव समाधान बनाने के लिए एआई, बड़े डेटा और टेलीहेल्थ का लाभ उठा रहे हैं।

एआई-संचालित निदानः रिवील हेल्थटेक जैसी कंपनियां एआई समाधान विकसित कर रही हैं जो ऑन्कोलॉजी और नैदानिक परीक्षणों जैसे क्षेत्रों में सहायता करने के लिए चिकित्सा छवियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) से संरचित डेटा को एकीकृत करती हैं।

टेलीहेल्थ और रिमोट केयरः टेलीहेल्थ को अपनाने से वृद्धि हुई है, जिससे दूरस्थ परामर्श और घर पर नैदानिक सेवाओं की अनुमति मिलती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ हो जाती है।

अनुसंधान और विकासः भारतीय अनुसंधान संस्थान स्वास्थ्य सेवा नवाचार को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने स्केलेबल, एआई-संचालित अनुप्रयोगों और कम लागत वाले निदान को विकसित करने के लिए अमेरिका में एलएसयू हेल्थ के साथ भागीदारी की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी उद्योग भागीदारों के लिए होमग्रोन प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सार्वजनिक अनुसंधान से बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए नवाचारों के हस्तांतरण में तेजी लाता है।

पारिस्थितिकी तंत्र ₹मेड इन इंडिया₹ अस्पतालों का उदय एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है जिसमें शामिल हैंः

मेडिकल डिवाइस पार्कः सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित कर रही है, जैसे कि नोएडा में, विनिर्माण और अनुसंधान के लिए हब बनाने के लिए, कंपनियों को नवाचार और पैमाने पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

सहायक नीतियांः सरकारी पहल और नीतियां, जैसे ₹चिकित्सा नवाचार- पेटेंट मित्र₹ पहल, पेटेंट प्रक्रिया को कारगर बनाने और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य नवाचारों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। अंत में, भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें ₹मेड इन इंडिया₹ अस्पताल और प्रभारी प्रौद्योगिकियों का नेतृत्व किया गया है। चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य में अत्याधुनिक नवाचारों के साथ सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके, देश एक ऐसा मॉडल बना रहा है जो न केवल अपनी स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को संबोधित करता है, बल्कि सुलभ और उच्च तकनीक वाले चिकित्सा समाधानों में एक वैश्विक नेता के रूप में भी स्थान देता है।

आपदा का अपराधी पहाड़ ही क्यों

सड़क पर विकराल होती बारिश ने कहर ढहाया या विकास ने आगे दौड़ पीछे चौड़ कर दी। जो भी हो मुसीबत के इस समय आंखों में सुरमा लगाए भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहाड़ के पत्थर नहीं कोसे, बल्कि कोसी लापरवाही जो जिंदा विकास के मुर्दाघरों को नीलाम करने पर तुली रही। गडकरी ने फोरलेन की डीपीआर के कान पकड़े हैं, तो हिमाचल को भी विकास के आईने साफ कर लेने चाहिएं। केंद्रीय मंत्री ने न आपदा के बीच क्रंदन किया और न ही तोहमतें इधर उछालीं, बल्कि पहाड़ पर निर्माण की ऐसी व्याख्या की जो विज्ञान और विमर्श के बीच अगली कई सदियों को माप सकती है, बशर्ते हर इंच पर आगे बढने की चुनौती को समझा जाए। अभी तो हमने पहाड़ पर विकास को केवल चिना है, न कि पहाड़ के लायक विकास को चुना है। पर्वतीय विकास की जिस इंजीनियरिंग की तरफ नितिन गडकरी इशारा कर रहे हैं, वह तो अभी शुरू ही नहीं हुई। फोरलेन परियोजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री का खुलासा सरासर लापरवाही तथा सार्वजनिक धन की सौदेबाजी है, लेकिन यह एक नियम के तहत बने तो मजमून बदलेगा। इस वक्त जलवायु परिवर्तन की सारी चुनौतियों का ठीकरा पहाड़ के सिर पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि देश आफत को समझने में अभी तक सचेत नहीं हुआ। आपदा का अपराधी हिमाचल ही क्यों बने। बेशक पहाड़ों को चीरा जा रहा है ताकि धूप आए और परिश्रम के गंतव्य में आर्थिक भूख मिट जाए, लेकिन यहां हर पेड़ अवैध तरीके से नहीं कटता। पेड़ भी काटता है हमारी रोजी रोटी और कहीं अचानक गिरकर तोड़ देता है जीने की राह पर सारी हड्डियां। जंगल या तो ज्यादा जंगली हो गए या जंगल को पर्यावरण का एकमात्र चिन्ह-प्रतीक मानने वालों ने सारे ताले पर्वतीय राज्यों पर लगा दिए। अपराधी पर्वत, जिसने अपनी तकदीर को जंगल बना लिया, उसे क्या मालूम बादलों का खेल। क्या समुद्र ने अपने भीतर सारी गर्मी को पहाड़ की तरफ धकेल दिया।

क्या मैदानी इलाके जब तपते हैं तो किसी ने पर्वत को रोका कि अपने हिमनद को मत पिघलाओ। पर्वत की छाती से निकलती नदियों को देश की लू जब सुखाती है, तो कौन मैदानी इलाकों को कहता है कि पर्यावरण के लिए प्रचंड गर्मी को रोको। क्या बरसात के दो-तीन महीनों में ही पर्यावरण का चिंतन मनन का दरिया बहने लगता है। शेष नौ महीनों के पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन दोषी। हिमाचल-उत्तराखंड की तरह सभी राज्यों को भी निर्देश दीजिए कि सभी आइंदा 70 फीसदी क्षेत्र में केवल वन उगाएं। हिमाचल के पड़ोसी मैदानी राज्य अगर 70 फीसदी जमीन में जंगलों की पैमाइश करें, तो मालूम हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण की धार कितनी नुकीली और कितने दबाव से भरी होती है। पर्वत के दबाव, पर्वत की आर्थिकी, पर्वत के रोजगार और पर्वत के विकास को समझने के इस आपदा का घर्षण काम नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने फोरलेन के परिप्रेक्ष्य में संभावना और सद्भावना का अलख जगा कर हिमाचल पर दोषारोपण नहीं किया, बल्कि यह स्वीकार किया है कि डीपीआर बनाने वालों ने विकास का सही आधार ढूंढने में कोताही बरती है। बेशक हिमाचल में हर तरफ के विकास में कोताही हुई। दूसरी ओर भारत सरकार पर्वतीय राज्यों के लगभग 45 लोकसभा क्षेत्रों की आवाज, जरूरतों और मजबूरियों को समझने में नाकाम रही है। अगर आपदा की लानतें पहाड़ पर थोपी जा रही हैं, तो इसके विकास और संरक्षण के लिए एक विशेष दृष्टि क्यों नहीं।

वृद्धावस्था की ओर बढ़ता भारत

इस दर में गिरावट के चलते वह दिन दूर नहीं, जब देश में कुल प्रजनन दर और नीचे चली जाएगी। इस विषय के जानकार लोगों का मानना है कि यदि भारत ने यह आंकड़ा छू लिया तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और फिर कुछ वर्षों में घटने लगेगी। बालिकाओं के गिरते लिंगानुपात के कारण भी यह स्थिति बनेगी

प्रकृतिजन्य जैविक घटना के अनुसार एक संतुलित समाज में बच्चों, किशोरों, युवाओं, प्रौढ़ों और बुजुर्गों की संख्या को एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अन्यथा यदि कोई एक आयु समूह की संख्या में गैर आनुपातिक ढंग से वृद्धि दर्ज हो जाती है तो यह वृद्धि उस संतुलन को नष्ट कर देगी, जो मानव समाज के विकास का प्राकृतिक आधार बनता है। भारत में जिस तेजी से बुजुर्गों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, वह आर्थिक व स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से तो संकट पैदा कर ही रही है, देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं के हित का एक बड़ा हिस्सा भी बुजुर्गों पर न्योछावर किया जा रहा है। संतुलित मानव विकास के लिए यह दुरभिसंधि घातक है। भारतीय आबादी के सिलसिले में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2023 ने देश में आबादी घटने के भयावह संकेत दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कामकाजी आयुवर्ग (15-59 वर्ष) की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, जबकि 0 से 14 आयुवर्ग की आबादी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यही नहीं, प्रजनन दर में कमी दर्ज की गई है। रपट के अनुसार वर्ष 1971 से 1981 के बीच 0-14 आयुवर्ग की हिस्सेदारी 41.2 फीसदी से घटकर 38.1 फीसदी रह गई है। जबकि 1991 से 2023 के बीच यह आंकड़ा 36.3 प्रतिशत से गिरकर 24.2 प्रतिशत रह गया है। महापंजीयक की ओर से जारी इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इसी अवधि में देश की कुल प्रजनन दर 1971 के 5.2 से घटकर 2023 में 1.9 रह गई है। एसआरएस ने इस रिपोर्ट में लगभग 88 लाख की नमूना जनसंख्या को दर्ज किया है।

इस कारण यह विश्व के सबसे बड़े जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों में से एक है। इसी 2018 के सर्वेक्षण में एक मां के उसके अपने जीवन काल में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.2 आंकी गई थी। अब 2023 के सर्वेक्षण में 1.9 रह गई है। इस दर में गिरावट के चलते वह दिन दूर नहीं, जब देश में कुल प्रजनन दर और नीचे चली जाएगी। इस विषय के जानकार लोगों का मानना है कि यदि भारत ने यह आंकड़ा छू लिया तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और फिर कुछ वर्षों में घटने लगेगी। बालिकाओं के गिरते लिंगानुपात के कारण भी यह स्थिति बनेगी। ये हालात सामाजिक विकृतियों को बढ़ावा देने वाले साबित हो सकते हैं। ऐसे में विवाह की उम्र बढ़ाने की जो चर्चा चल रही है, वह निकट भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। रपट के आंकड़े बताते हैं कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 0-14 आयुवर्ग में लडक़ों की संख्या लड़कियों से अधिक है, केवल दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को छोडक़र, यहां लड़कियों का अनुपात अधिक है। एसआरएस की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे जन्म के समय लिंगानुपात के हैं। जैविक तौर पर जन्म के समय सामान्य लिंगानुपात प्रति एक हजार बालिकाओं पर 1050 बालकों का रहता है या प्रति एक हजार बालकों पर 950 बालिकाओं का। बिगड़ा यह लिंगानुपात विवाह व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर डालता है। बिगड़ते लिंगानुपात के चलते इस स्थिति में सुधार के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। भारत इस अनुपात को सुधार सकता है, क्योंकि उसके पास 15 से 49 वर्ष के प्रजनन योग्य आयु वर्ग के लोगों का बड़ा समूह है।

इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विवाह की आयु घटाने के साथ अवैध संतान को वैधानिकता देना कानूनी रूप से अनिवार्य करना होगा। साथ ही लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण को कोख में ही नष्ट करने के उपाय सख्ती से बंद करने होंगे। इस हेतु आर्थिक समानता के उपायों के साथ युवाओं को प्रजनन, स्वास्थ्य शिक्षा और लैंगिक समानता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना होगा। अकसर भारत या अन्य देशों में बढ़ती आबादी की चिंता की जाती है। लेकिन अब भारत में कुछ धार्मिक समुदायों और जातीय समूहों में जनसंख्या तेजी से घटने के संकेत मिल रहे हैं। भारत में जहां आधुनिक विकास व विस्थापन के चलते पारसी जैसे धार्मिक समुदाय और आदिवासी प्रजातियों में आबादी घट रही है, वहीं उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचलन में आ जाने से एक बड़ा आर्थिक रूप से सक्षम समुदाय कम बच्चे पैदा कर रहा है। एक राष्ट्र के स्तर पर कोई देश विकसित हो या अविकसित हो अथवा विकासशील, जनसंख्या के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष एक प्रकार की सामाजिक व वैज्ञानिक सोच का प्रगटीकरण करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में जनसंख्या में बदलाव एक जैविक घटना होने के साथ-साथ समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आधारों को प्रभावित करने का कारण बनती है। इसलिए भारत में जब पांच अल्पसंख्यक समुदायों में से एक पारसियों की आबादी घटती है तो उनकी आबादी बढ़ाने के लिए भारत सरकार मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्लिमों को छोड़ अन्य धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के कठोर उपाय किए जाते हैं।

कक्षा 12 के बाद सही कैरियर कैसे चुनें

विजय गर्ग

करियर चुनने की यात्रा एक छात्र के जीवन के सबसे निर्णायक पहलुओं में से एक है, फिर भी यह अक्सर अनिश्चितता, सामाजिक अपेक्षाओं और सहकर्मी प्रभाव से घिरा होता है। एक ऐसे युग में जहां उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं और नए पेशे अभूतपूर्व गति से उभर रहे हैं, स्कूल के बाद ₹क्या करना है₹ तय करने का पारंपरिक दृष्टिकोण अब पर्याप्त नहीं है।

छात्रों को आज न केवल एक पेशे को सुरक्षित करने के लिए, बल्कि अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में स्पष्टता, आत्मविश्वास और उद्देश्य की खेती करने के लिए बहुत पहले से योजना बनाना शुरू करना होगा।

प्रारंभिक कैरियर योजना छात्रों को उन विकल्पों को बनाने में सक्षम बनाती है जो अच्छी तरह से सूचित और उनकी व्यक्तिगत ताकत, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हैं। KIIT वर्ल्ड स्कूल, गुरुग्राम की प्रिंसिपल नीलिमा कमराह ने कई प्रमुख तरीकों पर प्रकाश डाला, जिसमें शुरुआती करियर प्लानिंग इन सूचित निर्णयों को बनाने में छात्रों का समर्थन करती हैः

1. आत्म जागरूकता

व्यक्तिगत ताकत, हितों और मूल्यों को समझना कैरियर नियोजन की नींव है। शौक, परियोजनाएं, स्वयंसेवा और कार्यशालाएं जैसी गतिविधियाँ छात्रों को यह पता लगाने में मदद करती हैं कि वे वास्तव में क्या आनंद लेते हैं और उनके कौशल कहां झूठ बोलते हैं। आत्म-जागरूकता छात्रों को रुझानों या सहकर्मी दबाव का पालन करने के बजाय अपनी क्षमताओं और रुचियों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देती है।

2. कैरियर विकल्पों के लिए निर्यात प्रारंभिक योजना छात्रों को कैरियर के रास्तों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने का अवसर प्रदान करती है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और वाणिज्य जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से परे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, रचनात्मक उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोमांचक अवसर प्रदान करते हैं। इंटर्नशिप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और कैरियर मेले छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में पहले हाथ की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिसमें प्रत्येक के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता शामिल है।

3. स्पष्ट लक्ष्यों को सेट करना

प्राप्त मील के पत्थर में दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को तोड़ना छात्रों को केंद्रित और प्रेरित रखता है। उदाहरण के लिए, एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर सही विषयों की योजना बना सकता है, विज्ञान प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है, और व्यावहारिक ज्ञान को मजबूत करने वाली परियोजनाओं पर काम कर सकता है। इसी तरह, रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाला छात्र लेखन, डिजाइन, प्रदर्शन कला या डिजिटल सामग्री निर्माण में कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। स्पष्ट लक्ष्य छात्रों को उद्देश्य की भावना और पालन करने के लिए एक रोडमैप देते हैं।

4. बेहतर शैक्षिक विकल्प जो छात्र जल्दी योजना बनाते हैं, वे अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित सही स्ट्रीम, ऐच्छिक और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। शोध से पता चलता है कि जो छात्र सूचित शैक्षणिक विकल्प बनाते हैं, वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अपनी पढ़ाई से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। यह प्रारंभिक स्पष्टता बाद में पाठ्यक्रमों या धाराओं को स्विच करने की संभावना को भी कम करती है, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है।

5. कौशल विकास प्रारंभिक योजना छात्रों को अपने चुने हुए करियर के लिए प्रासंगिक संचार, टीमवर्क और समस्या-समाधान और तकनीकी कौशल दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। धीरे-धीरे, इन कौशलों का निर्माण छात्रों को उच्च शिक्षा और भविष्य की पेशेवर चुनौतियों के लिए तैयार करता है, जबकि आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है।

6. उन्नत निर्णय-निर्माण करियर विकल्पों की खोज और व्यक्तिगत शक्तियों का मूल्यांकन करने से छात्रों को महत्वपूर्ण सोच विकसित करने में मदद मिलती है। वे पेशेवरों और विपक्षों का वजन करना सीखते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं, और आवेगी विकल्पों के बजाय विचारशील निर्णय लेते हैं। यह निर्णय लेने की क्षमता न केवल करियर के लिए बल्कि दिन-प्रतिदिन के जीवन में भी उपयोगी है।

7. वित्तीय पुरस्कार और योजना

उच्च शिक्षा या विशेष पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को समझना प्रारंभिक कैरियर योजना का एक और लाभ है। छात्र और अभिभावक बजट की योजना बना सकते हैं, छात्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं, या पहले से लागत प्रभावी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। यह वित्तीय तनाव को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा और कैरियर विकल्प टिकाऊ हों।

8. कम तनाव और आत्मविश्वास निर्माण भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप अनिश्चितता और चिंता को कम करता है। छात्र उत्पादक चरणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। प्रारंभिक योजना एक सक्रिय मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, जो दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण हैः

प्रारंभिक कैरियर योजना केवल एक पेशा चुनने के बारे में नहीं है; यह अपने आप को समझने, अवसरों की खोज करने, लक्ष्यों को निर्धारित करने, कौशल विकसित करने और भविष्य के लिए व्यावहारिक रूप से तैयारी करने के बारे में है। जो छात्र विचारशील योजना में संलग्न होते हैं, वे सूचित निर्णय लेने, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास प्राप्त करने और स्पष्टता और आश्वासन के साथ अवसरों को गले लगाने के लिए बेहतर होते हैं। जब छात्र कैरियर की योजना में समय और प्रयास का निवेश करते हैं, तो वे आजीवन सीखने, आत्मविश्वास और सफलता के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं।

घायल चंबा की प्रधानमंत्री से उम्मीदें व पुकार

मैं यहां के सांसद-विधायकों से आग्रह करता हूं कि वे प्रधानमंत्री को इस आपदा के बारे में अवगत करवाएं जो यहां का दौरा कर जायजा लेकर, इस घायल आकांक्षी जिले को उठाने में मदद करें'

इस वर्ष हिमाचल प्रदेश ने ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया जिसने न सिर्फ यहां की धरती को छलनी किया, बल्कि पूरे देश और विदेश तक को झकझोर दिया। लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने चंबा जिले को गहरे जख्म दिए। उसी समय पवित्र मणिमहेश कैलाश यात्रा चल रही थी, जिसमें हजारों यात्री देश-विदेश से शामिल हुए थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और प्रशासन को मजबूरन यात्रा रोकनी पड़ी। यात्रियों को जहां भी ठिकाना मिला- गांवों, मंदिरों, गुरुद्वारों, पंचायत घरों, स्कूलों, आईटीआई संस्थानों, कॉलेजों और यहां तक कि स्थानीय लोगों के घरों में भी- वहीं रुकना पड़ा। इस विकट घड़ी में प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और आम जन ने यात्रियों को भोजन-पानी और आश्रय उपलब्ध कराया। चंबा की जनता ने हर फंसे यात्री को परिवार का हिस्सा समझकर सेवा दी। यह मानवता का अनुपम उदाहरण था, जिसने चंबा को 'प्रेरणा' बना दिया। लेकिन हालात इतने सरल नहीं थे। जगह-जगह भूस्खलन ने सडक़ें तोड़ीं, बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। चंबा देश-दुनिया से कट गया। हजारों यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई। इसी बीच मैं स्वयं अपने पारिवारिक कारणों से टांडा मेडिकल कॉलेज में था। बाहर से बैठा-बैठा मैं भीतरी बेचैनी और असहायता महसूस कर रहा था। रिश्तेदारों और यात्रियों के परिजनों के लगातार फोन आते, लेकिन चंबा से संपर्क टूट चुका था। मैंने सोशल मीडिया के जरिये और अन्य माध्यमों से सूचनाएं साझा कर, लोगों को धैर्य बंधाने का छोटा-सा प्रयास किया।

पांच दिन, दिन-रात यही कोशिश रही कि सही और प्रमाणिक समाचार परिजनों तक पहुंचे। धीरे-धीरे मौसम खुला। नेटवर्क और सडक़ें बहाल हुईं। यात्रियों के सकुशल वापस लौटने की खबरों से लोगों ने राहत की सांस ली। फिर भी यह यात्रा बहुत कठिन रही और कुछ अमूल्य जीवन छिन भी गए। भगवान शिव की कृपा रही कि बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिले ने गहरे घाव जरूर सहे। जब चंबा से तस्वीरें सामने आईं तो लगा मानो पूरा जिला घायल और जर्जर हो गया हो- सडक़ें नदारद, खेत बह गए, गांव बर्बाद हो गए, घर ढह गए। हर कोना यह पुकार रहा था कि कोई है जो मरहम लगाए, सहारा दे, बैसाखी थमाए। इस बीच प्रशासन और सरकार की भूमिका पर बहस भी हुई। कोई तारीफ करता, कोई आलोचना। लेकिन यह मानना होगा कि प्रशासन भी हम जैसे लोग ही होते हैं- सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने दिन-रात पैदल चलकर, भूखे रहकर यात्रियों और प्रभावितों तक पहुंचने का प्रयास किया। उनके इस समर्पण को सलाम है। सरकार के प्रतिनिधि भी चंबा पहुंचे, यात्रियों और स्थानीय लोगों का हाल जाना, राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को चंबा भेजा और स्वयं भी यहां आकर हालात पर नजर रखी। राहत व बचाव कार्य तेज हुआ, हवाई सेवाएं भी मुहैया करवाई गईं जिसके जरिये बहुत सारे यात्रियों को भरमौर से चंबा पहुंचाया गया। चंबा से पठानकोट-कांगड़ा के लिए सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सेवा दी। विधानसभा का मानसून सत्र बीच में छोड़ कर चंबा के सभी विधायक चंबा आ गए, जो अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस आपदा का जायजा लेकर पीड़ितों से मिले। लेकिन चंबा सदर के विधायक का इस पूरे प्रकरण में अपनी विधानसभा के साथ-साथ मणिमहेश यात्रा पर व समस्त जिले पर विशेष सहयोग व कार्य सराहनीय रहा जो दिन-रात इस आपदा में कार्य करते नजर आए।

कांगड़ा-चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज ने भी इस दौरान चंबा में आकर स्थिति का जायजा लिया। मंडी लोकसभा से निर्वाचित सांसद कंगना रणौत का सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान ही नजर आया, क्योंकि भरमौर विधानसभा का क्षेत्र मंडी लोकसभा का हिस्सा है, तो लोगों की आकांक्षाएं अपने सांसद से होती ही हैं। चंबा के बहुत लोकप्रिय कहे जाने वाले नेता राज्यसभा सांसद का भी इस दौरान सोशल मीडिया पर ही बयान सुनने को मिला जो व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को कोसते रहे, लेकिन इस आपदा में चंबा उन्हें भी दूर लगा। राजनीति से जुड़े सभी पार्टियों के नेताओं सहित पूर्व विधायक व मंत्री भी इस आपदा में सक्रिय रहे और इस आपदा में अपनी भूमिका अदा की। फिर भी एक सवाल बना रहा- क्या चंबा की पीड़ा केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? चंबा बार-बार केंद्र में विश्वास जताता है, भाजपा को चुनता है। तो केंद्र सरकार की विशेष नजर इस पिछड़े और आपदाग्रस्त जिले पर क्यों नहीं है? राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो हिमाचल में मौजूदा सरकार कांग्रेस की है और केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल भाजपा का चला हुआ हैष। बात चंबा की करें तो चंबा में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें मौजूदा समय में तीन क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा है। लोकसभा की बात करें तो लगातार तीन कार्यकालों से मंडी-चंबा लोकसभा में भी भाजपा का कब्जा है। यहां से लोकसभा सदस्य हर बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करते हैं। सीधा-सीधा कहा जाए तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि चंबा के लोग भाजपा को पहली पसंद मानते हैं, और दिल खोल कर समर्थन करते हैं।

हम सब जानते हैं कि जिला चंबा आकांक्षी जिलों में शामिल है और रही सही जो कसर थी इस आपदा ने पूरी कर दी। चंबा में जो विकास के कार्य हुए भी थे, वो सब इस आपदा की भेंट चढ़ गए। सभी सडक़ें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चंबा का एक-एक गांव इस आपदा में जर्जर हो गया है। फसलें-जमीनें सब बर्बाद हो गई हैं। ऊपर उठने की बजाय चंबा बहुत नीचे धंसता नजर आ रहा है। आज चंबा को आवश्यकता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर चंबा को विशेष राहत और पुनर्निर्माण पैकेज दें। यह धरती सिर्फ हिमाचल की नहीं, पूरे देश की है।

शिक्षा का विकल्प

विजय गर्ग

जबकि औपचारिक स्कूली शिक्षा सबसे आम रास्ता है, पारंपरिक शिक्षा के लिए कई विकल्प हैं जो व्यक्ति की सीखने की शैली और लक्ष्यों के आधार पर, यदि अधिक नहीं तो प्रभावी हो सकते हैं। ये विकल्प अक्सर हाथों पर अनुभव, व्यक्तिगत सीखने और एक मानकीकृत पाठ्यक्रम पर व्यावहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं। 1.। अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग यह शिक्षा का एक सदियों पुराना मॉडल है जो कक्षा के निर्देश के साथ ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण को जोड़ती है। अप्रेंटिसशिप विशेष रूप से नलसाजी, बिजली के काम, और निर्माण, साथ ही प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल जैसे पेशेवर क्षेत्रों में कुशल ट्रेडों में लोकप्रिय हैं। यह मार्ग व्यक्तियों को सीखने के दौरान मजदूरी अर्जित करने की अनुमति देता है और छात्र ऋ्रण के बोझ के बिना कार्यबल में एक सीधा मार्ग प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण समान है, पाठ्यक्रमों और हाथों पर काम के माध्यम से एक विशिष्ट नौकरी या व्यापार के लिए व्यावहारिक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। 2.। स्व-निर्देशित सीखना इंटरनेट के उदय के साथ, स्व-निर्देशित शिक्षा एक शक्तिशाली विकल्प बन गया है। यह दृष्टिकोण, अक्सर अनियंत्रित आंदोलन में देखा जाता है, शिक्षार्थी को अपनी शिक्षा के नियंत्रण में रखता है। वे अपने स्वयं के लक्ष्यों की पहचान करते हैं, अपने संसाधनों (ऑनलाइन पाठ्यक्रम, किताबें, वीडियो, संरक्षक) का चयन करते हैं, और अपनी गति निर्धारित करते हैं। यह विधि स्वामित्व की गहरी भावना को बढ़ावा देती है और व्यक्तियों को उन विषयों को आगे बढ़ाने की अनुमति देकर किसी विषय की अधिक गहन समझ पैदा कर सकती है जिनके बारे में वे वास्तव में भावुक हैं। 3। होमस्कूलिंग और लर्निंग पॉड्स

होमस्कूलिंग में शिक्षकों की भूमिका निभाने वाले माता-पिता और एक पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना शामिल है जो उनके बच्चे के हितों और सीखने की शैली को फिट करता है। यह एक लचीला और सहायक वातावरण प्रदान करता है। एक और हालिया विकल्प सीखने की फली है, जहां विभिन्न परिवारों के छात्रों का एक छोटा समूह एक साथ सीखने के लिए इकट्ठा होता है, अक्सर एक समर्पित ट्यूटर या माता-पिता के नेतृत्व वाले पाठ्यक्रम के साथ। यह एक पारंपरिक कक्षा के सामाजिक

संपर्क के साथ होमस्कूलिंग के व्यक्तिगत ध्यान को जोड़ती है। 4। अनुभवात्मक सीखना यह प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। किसी पुस्तक में किसी अवधारणा के बारे में पढ़ने के बजाय, आप इसे करके सीखते हैं। यह यात्रा और सांस्कृतिक विसर्जन से लेकर इंटर्नशिप, स्वयंसेवक काम या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने तक कई रूप ले सकता है। अनुभवात्मक सीखने में समस्या को सुलझाने, लचीलापन और अनुकूलनशीलता जैसे आवश्यक वास्तविक दुनिया कौशल विकसित होते हैं, जो कक्षा में दोहराना मुश्किल होता है। अंततः, ₹शिक्षा₹ के लिए सबसे अच्छा रास्ता विभिन्न दृष्टिकोणों का मिश्रण है। जबकि औपचारिक स्कूली शिक्षा एक संरचित नींव प्रदान करती है, जिसमें स्व-निर्देशित, अनुभवात्मक और व्यावसायिक सीखने के तत्वों को शामिल करना आधुनिक दुनिया के लिए अधिक अच्छी तरह से गोल, अनुकूलनीय और प्रासंगिक कौशल सेट हो सकता है।

नेक्स्टजेन जीएसटी सुधार केवल कर सुधार नहीं बल्कि राष्ट्र-निर्माण को तेज रफ्तार देने का परिचायक

कमलेश पांडेय

मौजूदा नेक्स्टजेन जीएसटी सुधार केवल कर सुधार नहीं बल्कि राष्ट्र-निर्माण को तेज रफ्तार देने का परिचायक है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थ भारत के सपनों को पंख लगाने वाला वह निर्णायक उपाय है जिसका सकारात्मक असर बहुत जल्द ही देश-दुनिया पर दिखाई पड़ेगा। बता दें कि 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक, जो गत 3 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित हुई, ने नेक्स्टजेन जीएसटी सुधारों की घोषणा की जिसके दृष्टिगत यह कहा जा सकता है कि यह भाजपा सरकार का एक साहसिक, ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है जिसने भारत की आधुनिक आर्थिक क्रांति के निर्माता के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत किया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक लाल किले के संबोधन में घोषित और आगामी 22 सितम्बर 2025 अर्थात नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने वाले ये सुधार वास्तव में 140 करोड़ भारतीयों के लिए राहत और समृद्धि का पर्व हैं। ऐसा इसलिए कि भाजपा नीत एनडीए के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने पुराने जटिल कर ढांचे को सरल बनाकर नागरिकों के अनुकूल 2-स्लैब संरचना में बदल दिया है। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर 18 प्रतिशत और केवल विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। इस प्रकार से यह वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है।

ऐसा होने से दैनिक आवश्यक वस्तुएँ जैसे- दूध, चावल, आटा, चाय, दही, किताबें और भारतीय रोटियाँ अब या तो कर-मुक्त हैं या सिर्फ 5 प्रतिशत पर कर लग रहा है। यह पीएम मोदी जी की गरीब और मध्यम वर्ग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है ताकि कोई भी भारतीय परिवार अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों से बोझिल न हो। यह भाजपा सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की प्रतिबद्धता का दोहराव भी है।

खास बात यह है कि अब स्वास्थ्य सेवाएँ भी सुलभ हुईं हैं क्योंकि सभी स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियाँ कर-मुक्त कर दी गई हैं और जीवनरक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इस प्रकार भाजपा नीत एनडीए सरकार ने आम आदमी के दुःख-दर्द के प्रति अपनी जो गहरी संवेदनशीलता दिखाई है और संकट की घड़ी में गरिमा और राहत सुनिश्चित की है, वह सराहनीय है। लगता है कि सरकार पर आरएसएस का बौद्धिक दबाव काम कर गया है।

आपको पता है कि किसान वर्ग जो भारत की रीढ़ समझे जाते हैं, सुधारों के केंद्र में हैं। उनके फायदे के लिए ही ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणालियों, खाद और कीटनाशकों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे खेती की लागत घटेगी और ग्रामीण समृद्धि बढ़ेगी। इससे स्पष्ट हो गया है कि यह लोकहितैषी सरकार वास्तव में किसानों के साथ खड़ी है।

वहीं, गृहिणियों और परिवारों को भी इस जीएसटी सुधार से सीधा लाभ मिला है। क्योंकि साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसी घरेलू वस्तुएँ अब सस्ती होंगी। इस प्रकार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यह कर दिखाया है कि वह हर भारतीय परिवार के सरल जीवन यापन (इज ऑफ लिविंग) की परवाह करती है और टैरिफ के मामले में अमेरिकी झटका लगने के बावजूद वह जनकल्याण को समर्पित है। यह आम भारतीयों के लिए सौभाग्य की बात है। आरएसएस-भाजपा जैसे जमीनी संगठनों से ऐसे ही सकारात्मक बदलाव की उम्मीद साल 2014 से ही की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है।

इस जीएसटी सुधार से युवा आकांक्षाओं की पूर्ति होने में भी मदद मिली है, क्योंकि छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी में कटौती से वे पहली बार खरीदारों के लिए सस्ती होंगी। वहीं, इनकी बढ़ती मांग से रोजगार भी पैदा होंगे, जो मोदी जी की युवा सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वहीं, हालिया बदलाव से तेज रफ्तार अवसंरचना विकास को भी बल मिलेगा, क्योंकि सीमेंट पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आमलोगों के घरों की लागत कम होगी और खास लोगों को भी अतिरिक्त बचत का मौका मिलेगा। इससे निकट भविष्य में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की गति बढ़ेगी, जिससे लाखों रोजगार सृजित होंगे। बतातें चलें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अवसंरचनात्मक विकास सिर्फ नीति नहीं बल्कि राष्ट्र-निर्माण का मजबूत मिशन भी है।

अर्थशास्त्रियों की राय है कि मौजूदा अभूतपूर्व जीएसटी बदलाव से एमएसएमई रोजगार की रीढ़ समझे जाने वाले छोटे छोटे व्यवसायों को भी काफी लाभ मिलेगा। इससे उनको आशातीत विकास का अवसर मिला है। वहीं, जीएसटी के सरल अनुपालन, एआई आधारित निगरानी और तेज़ रिफंड से कांग्रेस के लंबे उपेक्षा काल के बाद, भाजपा सरकार ने इन्हें नवाचार, विस्तार और मजबूती दी है जो सराहनीय पहल बताई जा रही है।

कहना न होगा कि ये सभी सुधार सीधे तौर पर भाजपा की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं का पूरक समझी जाती हैं। इसलिए लागत घटाकर और लालफीताशाही कम करके पीएम मोदी जी ने दिखाया है कि सुधार सिर्फ नारे से नहीं बल्कि वास्तविक कार्रवाई की वजह से आती हैं।

मौजूदा जीएसटी सुधार से कपड़ा और उर्वरक उद्योग जो लंबे समय से उल्टे कर ढांचे से जूझ रहे थे, को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें भी जीएसटी दरों के युक्तिकरण से सीधा लाभ मिलेगा। इस प्रकार यह न सिर्फ उद्योग को बढ़ावा देता है बल्कि भाजपा की निर्णायक और उत्तरदायी शासनशैली को भी दर्शाता है।

सरकार की इस पहल से मध्यम वर्ग का भी सशक्तिकरण होगा। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस, जिसने मध्यम वर्ग को टैक्स मशीन की तरह इस्तेमाल किया, उसके विपरीत भाजपा नीत एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्हें बेमिसाल राहत दी है, क्योंकि अब आवश्यक वस्तुएँ कर-मुक्त हैं और आकांक्षी वस्तुएँ सस्ती। इससे कारोबार में भी इजाफा होगा। वहीं, जीएसटी सरलीकरण से भारत की लॉजिस्टिक लागत कम हुई है जिससे भारतीय वस्तुएँ वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनी हैं। एक बार फिर, भाजपा के जीएसटी सुधारों ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दृष्टि को साबित किया है।

महत्वपूर्ण बात यह कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) दिसंबर 2025 तक शुरू किया जाएगा। इसके लिए भाजपा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वर्षों से झेली जा रही परेशानियों का अंत हो और व्यवसायों को न्याय, पारदर्शिता और तेज़ समाधान मिले। जहां तक महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण का सवाल है तो सरल जीएसटी और आसान क्रेडिट पहुँच से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को विस्तार, रोजगार और नवाचार का अवसर मिलेगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की 'नारी शक्ति भारत की प्रगति की चालक है' वाली सोच से जुड़ा है।

जहां तक इस सामूहिक सरकारी फैसले के सामूहिक आर्थिक प्रभाव का सवाल है तो नेक्स्टजेन जीएसटी सुधारों से जीडीपी में 1-1.2 प्रतिशत की वृद्धि और महंगाई में 1 प्रतिशत से अधिक की कमी का अनुमान है। यह भाजपा सरकार की विकास और स्थिरता के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सवाल है कि जब दुनिया मंदी से जूझ रही है, तब भाजपा शासन में भारत 7.8 प्रतिशत की दर से सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की निर्णायक और दूरदर्शी शासनशैली का प्रमाण है।

ऐसे में कहना न होगा कि यूपीए बनाम एनडीए का फर्क अब साफ महसूस किया जाएगा। क्योंकि यूपीए के दौर में जहां आटा, चावल और चाय पर वैट लगाया जाता था; वहीं अब एनडीए सरकार में वे कर-मुक्त हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने केवल वादे किए, जबकि भाजपा ने वास्तविक परिवर्तन लाकर दिखाया। और अंततः यह कहना समीचीन होगा कि नेक्स्टजेन जीएसटी सुधार केवल कर सुधार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र-निर्माण की तेज रफ्तार के परिचायक बन चुके हैं। ये पहल हर नागरिक को राहत, हर उद्योग को प्रोत्साहन देते हैं और भारत को 'विकसित भारत 2047' के सपने के और करीब ले जाते हैं। इस प्रकार यह महसूस किया जा सकता है कि देश में एक ही पार्टी की डबल इंजन सरकार और ट्रिपल इंजन सरकार बनने से विकास अब धरातल पर पहुंच चुका है। यह गरीबों की झोपड़ियों में भी बहुत जल्द ही दिखाई देने वाला है।

सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है पंजाब की बाढ़

राजेश कुमार पासी

इस समय हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब-हरियाणा विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहे हैं। देखा जाए तो भारी बारिश ने पूरे उत्तर-भारत में तबाही मचाई हुई है। टीवी मीडिया और सोशल मीडिया में आने वाले भयानक दृश्य देखकर पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं जिसके कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा इन पहाड़ी प्रदेशों में सड़कों और पुलों की जबरदस्त तबाही हुई है। इन प्रदेशों में जो बुनियादी ढांचा बर्बाद हुआ है, उसे दोबारा बनाने में काफी समय लगने वाला है। हरियाणा में भी बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है लेकिन पंजाब की बर्बादी परेशान करने वाली है। पंजाब की लगभग तीन लाख एकड़ भूमि बाढ़ के पानी में डूब चुकी है जिसके कारण फसलों की पूरी बर्बादी हो गई है। इसके अलावा कृषि भूमि में नदियों की रेत इस तरह से भर गई है कि दोबारा खेती करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी।

पंजाब के लगभग 2000 गांव बाढ़ में डूबने से भारी तबाही हुई है. मरे हुए मवेशियों की लाशें तैरती नजर आ रही हैं। इसके अलावा सैकड़ों मवेशी बाढ़ के पानी में बहकर पाकिस्तान जा चुके हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों की अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हिमालय से निकलने वाली जीवनदायिनी नदियों ने अपनी ताकत का अहसास करवाया है। पंजाब को बाढ़ से बचाने के लिए जो बांध बनाए गए थे, वो अपना काम करने में नाकाम रहे हैं। इसके विपरीत इन बांधो ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि जिन बांधों को बाढ़ से बचाव के लिए बनाया गया था, क्यों वो अपना काम नहीं कर पाए। पंजाब को पांच नदियों का प्रदेश कहा जाता है. इन नदियों के विकराल रूप ने न केवल भारतीय पंजाब बल्कि पाकिस्तान पंजाब को सहमा दिया है। पंजाब में हुए विनाश को देखते हुए केंद्र सरकार से जनता दखल देने की मांग कर रही है। इस समय पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को भोजन, दवाइयों और वित्तीय मदद की जरूरत है। पंजाब में क्रिकेटर, सिंगर, खिलाड़ी, अभिनेता और अन्य सेलिब्रिटी मदद के लिए आगे आए हैं जिससे राहत कार्य चल रहे हैं।

9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी पंजाब का दौरा कर रहे हैं जबकि केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पहले ही पंजाब का दौरा कर चुके हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पंजाब के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई राहत पैकेज घोषित किया जाए। केन्द्र सरकार की समस्या यह है कि भारत के बड़े हिस्से में बाढ़ से तबाही हुई है और सभी उससे राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पंजाब की समस्या ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है इसलिए केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। वैसे हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, इसलिए ऐसे मामले सुलझाने में समस्या आती है। पंजाब में विपक्ष की सरकार है इसलिए केन्द्र सरकार से राहत पैकेज के नाम पर इतनी राशि मांगी जा रही है, जिससे राहत पैकेज के बाद राजनीति की जा सके। देखा जाए तो ऐसी विभीषिका से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए लेकिन भारत में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि देशहित से ऊपर दलहित हो गया है। इस विभीषिका के लिए केन्द्र और राज्य की सरकारों को दलगत हितों से ऊपर उठकर काम करने

अभिव्यक्ति बनाम सुरक्षा: नेपाल की सड़कों पर उठे सवाल

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

[यू-टर्न की राजनीति : क्या सचमुच बदलेगी नेपाल की व्यवस्था?]

नेपाल की सड़कों पर उमड़ा जनाक्रोश और सरकार का यू-टर्न एक ऐसी कहानी बयां करता है, जो सत्ता और जनता के बीच तनाव, आधुनिक तकनीक की ताकत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नई पीढ़ी के उबलते गुस्से को उजागर करती है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, फर्जी खबरों और साइबर अपराधों पर नियंत्रण का हवाला देकर उचित ठहराया। मगर इस फैसले ने देश के युवाओं, खासकर जेन-जी को, सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। भ्रष्टाचार, असमानता और बेरोजगारी के खिलाफ पहले से सुलग रहा आक्रोश इस प्रतिबंध के बाद ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हिंसक प्रदर्शनों में 20 लोगों की मौत और 340 से अधिक के घायल होने के बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सोमवार देर रात कैबिनेट की आपात बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की कि सोशल मीडिया प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है।

नेपाल सरकार का सोशल मीडिया पर पाबंदी का निर्णय शुरू में प्रशासनिक सख्ती का कदम लगता था। सरकार का दावा था कि मेटा, अल्फाबेट और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण नहीं कराया। 28 अगस्त से दी गई सात दिन की समयसीमा के बावजूद इन कंपनियों ने नियमों का पालन नहीं किया। सरकार ने इसे फर्जी आईडी, नफरत फैलाने वाली सामग्री और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने का जरिया बताया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में दलील दी कि एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया। यह तर्क सतही तौर पर जायज लग सकता है, मगर आलोचकों और युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना। नेपाल जैसे देश में, जहां 1.35 करोड़ फेसबुक और 3.6 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, सोशल मीडिया केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि कारोबार, शिक्षा और सामाजिक बदलाव का मजबूत मंच है।

प्रतिबंध का असर तीखा और विनाशकारी था। काठमांडू से पोखरा, दमक और भैरहावा तक सड़कों पर हजारों युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह सिर्फ सोशल मीडिया की बंदिश का गुस्सा नहीं था, बल्कि दशकों से जड़ जमाए भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और आर्थिक असमानता के खिलाफ संचित आक्रोश का ज्वालामुखी था। डिजिटल युग में जन्मे जेन-जी (1997-2012) ने इसे अपनी आवाज कुचलने की साजिश माना। "भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं" और "जनता की हताशा चरम पर" जैसे नारों ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन केवल प्रतिबंध के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ था, जो युवाओं को अवसरों से वंचित रखती है। संसद भवन में प्रदर्शनकारियों का घुसना, पुलिस बैरिकेड्स का तोड़ा जाना और हिंसक झड़पें इस बात का सबूत थीं कि जनता का सब्र टूट चुका है।

सरकार का यू-टर्न इस तूफान का तात्कालिक जवाब था, लेकिन क्या यह काफी है? प्रतिबंध का फैसला राष्ट्रीय हितों की आड़ में लिया गया, मगर यह जल्दबाजी और असंवेदनशील कदम साबित हुआ। नेपाल, जहां 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बावजूद भ्रष्टाचार और अस्थिरता की शिकायतें थमती नहीं, वहां सोशल मीडिया जनता की सबसे मुखर आवाज बन चुका है। इसे बंद करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार था और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। न्यायालय ने भी चेताया था कि कैबिनेट के फैसले से सोशल मीडिया पर पाबंदी गलत है, फिर भी ओली सरकार ने यह जोखिम उठाया।

दूसरी ओर, सरकार ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर अनियंत्रित सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। फर्जी खबरें, नफरत भड़काने वाली पोस्ट और साइबर अपराध निस्संदेह गंभीर मुद्दे हैं। मगर क्या इनका समाधान पूर्ण प्रतिबंध था? सरकार ने टिकटॉक और वाइबर जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के बाद छूट दी, जबकि फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे बड़े मंचों पर पाबंदी लगा दी। इस दोहरे रवैये ने पारदर्शिता की कमी को जनता के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया। अगर नियमन ही मकसद था, तो सरकार कानूनी ढांचा बनाकर या तकनीकी उपायों से इसे हासिल कर सकती थी। इसके बजाय, उसने ऐसा कदम उठाया, जिसने लाखों नेपाली नागरिकों—खासकर विदेश में रहने वाले और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर निर्भर लोगों—को गहरे तक प्रभावित किया।

प्रतिबंध हटाना सरकार की मजबूरी और जनता की ताकत की जीत माना जा सकता है। फिर भी, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का यह बयान कि सरकार को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, सत्ता के अहंकार को उजागर करता है। यह रवैया जनता के गुस्से को और हवा दे सकता है। प्रधानमंत्री ओली ने हिंसा की जांच के लिए 15 दिन में रिपोर्ट देने वाली समिति गठित करने की बात कही, मगर क्या यह समिति भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता जैसे जड़मूल मुद्दों का सामना कर पाएगी? या यह महज एक और दिखावटी कदम साबित होगा?

जेन-जी का यह आंदोलन महज सोशल मीडिया की बहाली का संघर्ष नहीं है; यह उस व्यवस्था के खिलाफ बगावत है, जो युवाओं को अवसरों से वंचित रखती है और नेताओं को जवाबदेही से बचाती है। नेपाल में 70 साल से अधिक उम्र के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों का साया मंडराता रहा है, और अब युवा पीढ़ी निर्णायक बदलाव की मांग कर रही है। 'हामी नेपाल' जैसे स्वतंत्र समूहों ने इस आंदोलन को दिशा दी, बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक दल के समर्थन या बाहरी एजेंडे के। यह जनता की हताशा और उम्मीद का प्रबल प्रतीक है, जो एक नए नेपाल का सपना देखता है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध एक भूल थी, जिसने जनता के गुस्से को आग की तरह भड़का दिया और हिंसा को जन्म दिया। सरकार का यू-टर्न उसकी मजबूरी था, लेकिन यह जनता की अडिग ताकत का भी प्रमाण है। मगर यह आंदोलन केवल डिजिटल मंचों तक सीमित नहीं है—यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ एक व्यापक जंग है। जांच समिति का गठन एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर सरकार इन जड़मूल मुद्दों को नजरअंदाज करती है, तो यह आग फिर लपटें उठाएगी। नेपाल की यह घटना एक कड़ा सबक है: डिजिटल युग में जनता की आवाज को दबाना असंभव है, और सत्ता को जवाबदेह बनाना आज की पीढ़ी का संकल्प है।

मौन से संवाद तक आलेख)

सुनील कुमार महला

हर वर्ष 10 सितंबर को 'विश्व आत्महत्या निवारण दिवस' मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य आत्महत्या को रोकने(टू प्रिवेंट सुसाइड) के लिए जागरूकता फैलाना है। पाठकों को बताता चलूं कि यह दिवस इंटरनेशनल एसोसिएशन फोर सुसाइड प्रिवेंशन (आईएएसपी) द्वारा 2003 से मनाया जा रहा है।विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ)इसमें अपना सहयोग देता है।इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आत्महत्या से होने वाली मौतों को कम करना, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात करना, समर्थन, देखभाल और उपचार की पहुँच बढ़ाना तथा आत्महत्या करने वाले लोगों, उनके परिवारों और दोस्तों को सहायता देना है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि 2024 से 2026 तक विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का त्रिवार्षिक विषय 'आत्महत्या पर कथा को बदलना' है, जो आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली चर्चा का आग्रह करता है, कलंक को समझ और समर्थन के साथ बदलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय विषयः 'चेंजिंग द नेरेटिव आन सुसाइड '(आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना) रखी गई है। कहना ग़लत नहीं होगा कि यह विषय आत्महत्या के बारे में हमारी सोच और संवाद को बदलने की आवश्यकता को उजागर करता है। पाठक जानते हैं कि विश्व में हर वर्ष लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। मानसिक तनाव, अवसाद, नशा, आर्थिक समस्याएँ, अकेलापन और सामाजिक दबाव इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आत्महत्या एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है – इसे छिपाना नहीं, समझना ज़रूरी है। बहरहाल, यदि हम यहां पर भारत में आत्महत्या के प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो भारत में 2022 में कुल 1,70,924 आत्महत्याएँ हुईं, जो 2021 की तुलना में 3.3% अधिक हैं। चिंताजनक बात यह है कि यह आंकड़ा पिछले 56 वर्षों में सबसे अधिक है। आत्महत्या की दर की यदि हम यहां पर बात करें तो साल 2022 में आत्महत्या की दर 12.4 प्रति 1,00,000 जनसंख्या थी। वास्तव में यह बहुत ही चिंताजनक बात है कि 18-30 वर्ष की आयु वर्ग में कुल आत्महत्याओं का 35% हिस्सा है, जबकि 30-45 वर्ष की आयु वर्ग में 32% आत्महत्याएँ हुईं। वहीं दूसरी ओर यदि हम महिलाओं में आत्महत्या की यदि यहां पर बात करें तो महिलाओं में आत्महत्या की दर 80 प्रति 1,00,000 है, जबकि पुरुषों में यह दर 34 प्रति 1,00,000 है। इतना ही नहीं साल, 2022 में 11,290 किसानों और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्याओं का 6.6% है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे कि अवसाद, चिंता, द्विध्रुवी विकार, और स्किज़ोफ्रेनिया, आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं।यह भी एक तथ्य है कि कृषि संकट, जैसे सूखा, फसल विफलता, और कर्ज़ का बोझ, किसानों में मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि का कारण बनते हैं। हाल फिलहाल, आत्महत्या का निवारण एक बहुत ही संवेदनशील और बहुस्तरीय विषय है। आत्महत्या से बचाव केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि परिवार, समाज, स्वास्थ्य तंत्र और नीति निर्माण का साझा दायित्व है। आज जरूरत इस बात की है कि हम विशेष रूप से अपने युवाओं में अवसाद (डिप्रेशन), चिंता (एंग्ज़ायटी), नशे की आदत जैसी समस्याओं की समय रहते पहचान करें। समय पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी और आवश्यक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि योग, ध्यान, व्यायाम और सकारात्मक सोच से मानसिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। आज हमारी कमी यह है कि हम दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। होना तो यह चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को सुनें, उसका कभी भी मज़ाक न उड़ाएँ। अकेलेपन, असफलता, तनाव, पारिवारिक झगड़े आदि पर खुलकर बातचीत करें। यदि कोई व्यक्ति तनाव और अवसाद से पीड़ित है तो हमें यह चाहिए कि हम उस व्यक्ति विशेष को 'तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं' जैसा भरोसा दें, ताकि वह जीवन में सहज हो सके और उसे तनाव और अवसाद महसूस न हो।बच्चों, किशोरों और युवाओं के साथ क्वालिटी टाइम बिताया जा सकता है। हमें यह चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए भी पर्याप्त समय निकालें और उन पर पर्याप्त ध्यान दें। बच्चों की दिनचर्या, उनके व्यवहार और मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोबाइल की लत तनाव और अवसाद का बड़ा कारण हो सकती है। हमें यह चाहिए कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने का प्रयास करें और उन्हें खेल के मैदानों, नैतिक कहानियों, पुस्तकालयों, हमारी सनातन संस्कृति आदि से जोड़ें।संकट की स्थिति में उन्हें दोषी न ठहराकर उनकी सहायता करें। उन्हें संबल दें।

बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करना बहुत ही जरूरी है। वास्तव में, सकारात्मक सोच वह मानसिक शक्ति है जो हमारे दृष्टिकोण, व्यवहार और जीवन की दिशा बदल देती है। यह सिर्फ सोच बदलने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो कठिनाइयाँ भी अवसर बन जाती हैं। सकारात्मक सोच का फायदा यह है कि यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे तनाव और अवसाद को कम करती है तथा यह हमारी प्रोडेक्टीविटी (उत्पादकता) में इजाफा करती है। वास्तव में,सकारात्मक सोच का जादू कोई असंभव चीज़ नहीं है। यह रोज़मर्रा की आदतों से पैदा होता है। शुरुआत छोटे कदमों से की जा सकती है, फिर धीरे-धीरे हमारी सोच, दृष्टिकोण और जीवन में बदलाव साफ दिखाई देंगे। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि एक सकारात्मक विचार पूरी दुनिया बदल सकता है और इसकी शुरुआत हम अपने भीतर से कर सकते हैं। इसके अलावा, शराब, ड्रग्स और अन्य लत मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। नशा छुड़ाने के लिए पेशेवर सहायता ली जा सकती है। बच्चों में जीवन कौशल का विकास किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं,समस्या समाधान की क्षमता विकसित की जानी चाहिए तथा बच्चों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन, भावनाओं को संभालने और तनाव कम करने की तकनीकें सीखना भी जरूरी है। हमारी ओर से सामाजिक समर्थन और नीतिगत पहलें की जानी चाहिए। मसलन, क्लब, खेल, सामाजिक समूहों में शामिल होकर सकारात्मक नेटवर्क बनाए जाने चाहिए तथा मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आसान उपलब्धता आवश्यक है।स्कूलों और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि भारत सरकार ने आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। मसलन,आज हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 लागू है। इस अधिनियम ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों को सहायता प्राप्त करना आसान हुआ है। गौरतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा करने और भारत के मानसिक स्वास्थ्य कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ एकीकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का स्थान लिया और भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं में कई प्रगतिशील बदलाव पेश किए, जैसे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार और भारत में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। इतना ही नहीं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा 'किरण' की भी शुरुआत की है। यह हेल्पलाइन चिंता, तनाव, अवसाद और आत्मघाती विचारों से जूझ रहे व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है। यह सेवा 13 भाषाओं में उपलब्ध है और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा संचालित है, जो उपयोगकर्ताओं को परामर्श, मार्गदर्शन और आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सहायता प्रदान करते हैं। मनोदर्पण पहल भी एक अन्य पहल है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह पहल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करती है। इसमें ऑनलाइन परामर्श, वीडियो, पॉडकास्ट और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी शामिल है, जो मानसिक तनाव और चिंता से निपटने में मदद करती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, 2022

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता, शिक्षा, और आपातकालीन सेवाओं के समन्वय पर केंद्रित है। इस रणनीति का उद्देश्य आत्महत्या की दर को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है। अंत में यही कहूंगा कि जीवन अनमोल है और हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमें जीवन सेवा, प्रेम, करुणा और आत्म-विकास के लिए दिया है।हमें यह जीवन मिला है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर दिन, हर सांस, एक नया अवसर है।हमें मानसिक स्वास्थ्य(मेंटल हेल्थ) पर खुलकर बात करनी चाहिए, और इस कलंक को समाप्त करना चाहिए और हर उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो संघर्ष कर रहा हो। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम करुणा, संवाद और सहयोग से जीवन को नई दिशा दें। यही सच्चा संकल्प है – 'जीवन को चुनें, आशा को बढ़ावा दें।' हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि हमारी सोच जितनी उजली होगी, हमारी राह उतनी ही सरल होगी।

नहीं की बेटे - बहू ने देखभाल, कानपुर में 5 दिन बाद घर से मिला बुजुर्ग का शव

सुनील बाजपेई

कानपुर। जो मां-बाप सारी परेशानियों और कष्ट सहकर अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करते हैं। पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बनाते हैं। वही बच्चे बुजुर्ग हो जाने पर अपने मां-बाप का ख्याल तक नहीं रखते ,जिसके फलस्वरुप ऐसे कई बुजुर्ग बड़े कष्टमय हालातों में मौत का वरण करने के लिए भी मजबूर होते हैं।

कुछ ऐसा ही लगभग 70 साल की सुरेंद्र आहूजा के साथ भी हुआ। उनकी लाश उनके ही घर से 5 दिन बाद बरामद की गई। उनके दोनों बेटे और बहू बाहर रहते हैं। बताते हैं कि काफी समय से उन्होंने अपने बुजुर्ग आप का कोई हाल-चाल नहीं लिया था।

इस घटना का संबंध नजीराबाद थाना क्षेत्र से है जहां कौशलपुरी इलाके में हनुमान मंदिर के पास घर में पांच दिन पुराना बुजुर्ग सुरेंद्र आहूजा (68) का आज मंगलवार दोपहर शव उनके ही घर में मिला। इसकी जानकारी घर से आ रही दुर्गंध के के बाद हुई जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की।

पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र आहूजा पिछले 10 साल से अकेले घर में रह रहे थे। जबकि उनका बेटा करण दिल्ली में रहता है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक करण ने इधर काफी अरसे से अपने पिता का हाल-चाल तक नहीं लिया था। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

इन्दौर के युवा भजन गायक अंश जैन को राजस्थान में "स्वर सम्राट" की उपाधि से सम्मानित किया गया।

श्री 1008 चन्द्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर शिवाड़ सवाईमाधोपुर राजस्थान में श्री कल्पद्रुम महामण्डल विधान एक विश्वशांति महायज्ञ अनुष्ठान के समापन के अवसर पर संकल दिगम्बर जैन समाज शिवाड़ सवाईमाधोपुर समाज ने इन्दौर के युवा जैन भजन गायक "स्वर सम्राट" अंश जैन को स्वर सम्राट उपाधि से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिवाड़ दिगम्बर जैन समाज के दिनेश जैन, महेश कुमार जैन, आशीष जैन, दीपक जैन, संदीप जैन, अंकित जैन और सभी समाजजन और कमेटी के पदाधिकारी व समस्त समाज जन इस अलंकृत समारोह में शामिल हुऐ।

"मैं ठीक हूँ" का मुखौटा और भीतर का शून्य

[हर आत्महत्या समाज की असफलता की गवाही है]

जब अंधेरा अपने चरम पर पहुंचता है, तो वह न केवल आंखों को, बल्कि आत्मा को भी निगल लेता है। वह क्षण, जब मन की चीखें बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंचतीं, जब मुस्कान के पीछे छिपा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता, और जब इंसान अपनी सांसों से ही हार मान लेता है, यही वह पल है जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हमें झकझोरता है, जागने को विवश करता है। आत्महत्या कोई क्षणिक निर्णय नहीं, बल्कि वर्षों की उपेक्षा, अनसुनी पीड़ा और टूटे सपनों से रिसता हुआ धीमा जहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, हर साल लगभग 7,00,000 जिंदगियां आत्महत्या के कारण खामोश हो जाती हैं, हर 40 सेकंड में एक जीवन रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। भारत में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 1,70,000 से अधिक लोग इस अंधेरे में खो गए, जिनमें युवा और मध्यम आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित रहे। ये आंकड़े महज संख्याएं नहीं, बल्कि अनकहे दर्द, अनसुनी कहानियों और अनदेखे आंसुओं की मूक गवाही हैं।

हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां तकनीक ने हमें जोड़ा तो है, पर आत्मीयता की डोर को कमजोर कर दिया है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों की भीड़ हो सकती है, लेकिन दिल की गहराइयों को सुनने वाला एक भी साथी मुश्किल से मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य आज भी हमारे समाज में एक अनदेखा, अनछुआ विषय है। अवसाद को कमजोरी, चिंता को अतिशयोक्ति और उदासी को क्षणिक मूड समझकर टाल दिया जाता है। लेकिन ये भावनाएं, अगर समय पर न सुनी जाएं, तो एक ऐसी खाई बन जाती हैं, जहां से वापसी की राह धुंध में खो जाती है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 75% लोग, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, उन्हें उचित चिकित्सा या सहायता नहीं मिलती। भारत में यह संकट और गहरा है, जहां प्रति 1,00,000 लोगों पर केवल 0.3 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। यह कमी केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि हमारी संवेदनशीलता और प्राथमिकताओं की कमी को भी उजागर करती है।

आत्महत्या की ओर बढ़ता हर कदम एक अनुत्तरित सवाल छोड़ जाता है, क्या हम वाकई अपने आसपास के लोगों को देख पाते हैं? क्या उनकी चुप्पी की गहराई को समझ पाते हैं? समाज में सफलता की चमक को तो हम तालियों से नवाजते हैं, पर असफलता की ठोकर से टूटे मन की पुकार को अनसुना कर देते हैं। हम बच्चों से ऊंचे अंक मांगते हैं, पर उनकी मानसिक थकान को नजरअंदाज करते हैं। रिश्तों की छोटी-छोटी दरारों को हम मामूली समझ लेते हैं, जो धीरे-धीरे आत्मा को चूर-चूर कर देती हैं। एक अध्ययन बताता है कि भारत में 40% से अधिक आत्महत्या के मामलों में पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव जड़ में हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ढांचे

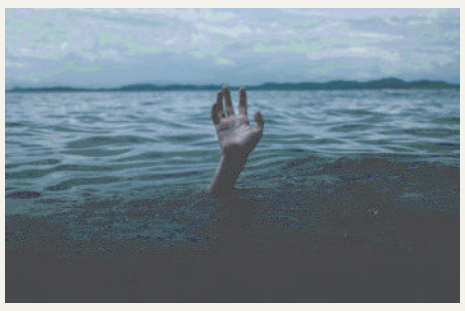

की खामियों की मूक गवाही हैं।

जीवन की कीमत सिर्फ सांसों से नहीं, बल्कि उन संवेदनाओं से मापी जाती है जो हर धड़कन में बसती हैं। हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द, हर चुप्पी में दबी पुकार—इन्हें सुनना ही सच्ची मानवता है। "मैं ठीक हूँ" का जवाब हमेशा सच नहीं होता; यह अक्सर एक मुखौटा है, जो टूटे मन को छिपाता है। हमें सीखना होगा कि इस मुखौटे के पीछे की सच्चाई को कैसे पढ़ा जाए। मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियाँ कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, हमें यही संदेश देता है—जागरूकता ही नहीं, बल्कि करुणा और संवेदनशीलता के साथ एक-दूसरे का साथ देना। एक साधारण सवाल, "तुम सचमुच कैसे हो?" किसी की जिंदगी को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है।

आत्महत्या रोकथाम केवल चिकित्सा या परामर्श तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो किसी की जिंदगी का हिस्सा है। एक सच्चा दोस्त जो बिना आलोचना के सुने, एक परिवार जो बिना शर्त प्यार दे, एक सहकर्मी जो प्रतिस्पर्धा में भी इंसानियत न भूले—ये छोटे-छोटे कदम किसी के जीवन में उजाला ला सकते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन (आईएएसपी) बताता है कि सामुदायिक समर्थन और खुला संवाद आत्महत्या रोकथाम में सबसे प्रभावी हथियार हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, जिन्हें अपने आसपास भावनात्मक सहारा मिला, उनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति 50% तक कम हुई। यह आंकड़ा चीख-चीखकर कहता है कि हमारी एक छोटी-सी कोशिश, किसी को यह यकीन दिलाना कि उसका वजूद अनमोल है, एक जिंदगी को अंधेरे से रोशनी की ओर मोड़ सकती है।

आज के दौर में, जब तनाव और अवसाद की छाया तेजी से फैल रही है, मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्व देना अनिवार्य है। स्कूलों में बच्चों को न केवल गणित और विज्ञान, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की कला भी सिखानी होगी। कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और खुली बातचीत को प्रोत्साहन देना होगा। परिवारों में ऐसी सुरक्षित जगह बनानी होगी, जहां हर सदस्य बिना डर के अपनी कमजोरियों को साझा कर सके। भारत में, जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सामाजिक कलंक अब भी गहरा है, यह बदलाव और भी जरूरी है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2021 के अनुसार, 19.73 करोड़ से अधिक भारतीय मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन केवल 10% को ही उचित सहायता मिलती है। यह खाई हमें चेताती है कि हमारी प्राथमिकताएं कहीं भटक रही हैं।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हमें याद दिलाता है कि हर जिंदगी अनमोल है। हर वह व्यक्ति, जो इस दुनिया को छोड़ गया, उसके सपने, उसकी हंसी, उसके अनकहे शब्द हमारे बीच जीवित रह सकते थे, अगर हमने समय पर उनकी मूक पुकार सुन ली होती। आत्महत्या की खबरें महज सुर्खियां नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जवाबदेही की चेतावनी हैं। हमें एक ऐसा समाज गढ़ना होगा, जहां उदासी को छिपाने की जरूरत न पड़े, जहां आंसुओं को कमजोरी न समझा जाए, और जहां अवसाद से जूझना हार नहीं, बल्कि इंसान होने का प्रमाण माना जाए।

यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक निरंतर संकल्प है—हर उस इंसान के लिए, जो अकेलेपन की सर्द रातों में खोया है। एक फोन कॉल, एक साधारण संदेश, एक गर्मजोशी भरा स्पर्श—ये छोटे-छोटे कदम किसी को यह अहसास दिला सकते हैं कि वह अकेला नहीं। जब हम किसी के अंधेरे में एक छोटा-सा दीप जलाते हैं, तो हम न केवल एक जिंदगी बचाते हैं, बल्कि मानवता की सबसे खूबसूरत मिसाल रचते हैं।

आत्महत्या रोकथाम का रास्ता लंबा है, पर इसकी शुरुआत साधारण कदमों से हो सकती है। हमें अपने आसपास के लोगों को देखना सीखना होगा—उनके शब्दों से ज्यादा उनकी चुप्पी को, उनकी हंसी से ज्यादा उनकी आंखों की उदासी को। हमें यह भरोसा जगाना होगा कि कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं कि उसे साझा न किया जा सके। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हमें यही संदेश देता है—हर जिंदगी कीमती है, और उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए, इस दिन को एक संकल्प बनाएं: हम न केवल अपने लिए, बल्कि एक-दूसरे के लिए जिएंगे, ताकि कोई आत्मा अंधेरे में न खो जाए।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

झारखंड में पेसा कानून लागू होने तक बालू समेत लघु खनिजों की नीलामी अधर मे लटका

हाईकोर्ट ने पंचायती सचिव से पूछा- क्या सीएम और मंत्रियों को जेल भेज दें ?

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट यानी ₹पेसा ₹ कानून न लागू किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मंगलवार को सख्त आदेश पारित किया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में पेसा कानून लागू होने तक बालू घाट सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों की नीलामी पर रोक लगा दी है। रांची, 9 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट) कानून न लागू किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मंगलवार को सख्त आदेश पारित किया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में पेसा कानून लागू होने तक बालू घाट सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों की नीलामी पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार कोर्ट में उपस्थित हुए। उनके जवाब से असंतुष्ट होकर खंडपीठ ने सख्त लहजे में पूछा- "क्या आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें? क्या यही सुझाव है आपका?" कोर्ट ने टिप्पणी की बात राज्य सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को कमजोर कर रही है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार स्थानीय निकायों को मिलने चाहिए, लेकिन सरकार नियमावली लागू करने में लगातार टालमटोल कर रही है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पेसा नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिस पर आपत्ति और सुझाव लिए गए हैं। अब नियमावली को तैयार कर कैबिनेट और मुख्यमंत्री की स्वीकृति ली जानी है। इस जवाब पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने तर्क दिया कि राज्य सरकार जानबूझकर पेसा नियमावली को अधिसूचित करने में देर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बालू घाटों और अन्य लघु खनिज खदानों की दीर्घकालिक नीलामी व पट्टे देने की प्रक्रिया में जुटी है। जब तक नियम बनेंगे, तब तक ग्राम सभाओं के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने जुलाई, 2024 में एक

जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड सरकार को दो माह के अंदर राज्य में पेसा नियमावली अधिसूचित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्यों के अनुरूप तथा पेसा कानून के प्रावधान के अनुसार पेसा नियमावली बनाकर लागू किया जाये। इस आदेश का अनुपालन अब तक होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दायर की है। इसके पहले इस याचिका पर 5 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक पेसा नियमावली लागू क्यों नहीं हुई? इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई? इस पूरे मामले पर सरकार को विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में झारखंड में परलैंगिक कल्याण बोर्ड की बैठक

ट्रांसजेंडरों का राज्यव्यापी सर्वे कराएं: अल्का तिवारी, मुख्यसचिव, झारखंड

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ट्रांसजेंडरों का राज्यव्यापी सर्वे कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे से ही पता चलेगा कि ट्रांसजेंडरों की जिलावार संख्या क्या है। उनकी जरूरतें क्या हैं। वे क्या चाहते हैं। उसके बाद ही उनके कल्याण के लिए फंड और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में सहूलियत होगी। साथ ही उनके लिए तय विभिन्न योजनाओं से उन्हें जोड़ना भी सुगम होगा। वह मंगलवार को अपनी अध्यक्षता में आहूत झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक कर रही थीं।

बैठक में यह बात उभर कर सामने आयी कि ट्रांसजेंडर खुलकर सामने आने से हिचकिचाते हैं। वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। इससे उनका पहचान पत्र बनाने, आरक्षण का लाभ देने, पेंशन योजना से जोड़ने, आयुष्मान कार्ड से जोड़ने, गरिमा गृह निर्माण करने, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण देने आदि का काम प्रभावित होता है। मुख्य सचिव ने इसके निराकरण के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिलास्तरीय समिति के यथाशीघ्र गठन पर बल दिया।

वर्ग के लोगों के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड इसमें सहयोग करता है। बोर्ड विभिन्न विभागों को ट्रांसजेंडरों से संबंधित योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है।

मालूम हो कि पूरे देश में ट्रांसजेंडरों की कुल संख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) 4,87,803 है। झारखंड में उनकी संख्या 13,463 है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में गृह सचिव श्रीमती वंदना दादेल, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सचिव मनोज कुमार, वित्त सचिव प्रशान्त कुमार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे

मंत्री दीपक बिरूवा समेत अन्य नेताओं ने गुआ शहीद स्थल पर दी श्रद्धांजलि

1980 में सिंहभूम के आदिवासियों पर बिहार मिलिट्री पुलिस की जघन्यतम हिंसक कारवाई

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

गुवा, इलाके के हो समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, चाईबासा सीट के माणकी परिवार से विधायक, संप्रति झारखंड के कद्दावर मंत्री दीपक बिरुवा ने गुआ शहीद स्थल पर पहुंच कर पारंपरिक तरीके से उन शहिदों को श्रद्धांजलि दी जिन आठ अलग राज्य संग्रामी लोगों को तत्कालीन बिहार सरकार की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से मौत के घाट 8 अगस्त 1980 में उतार दिया था। तब जब वे अपनी पुरानी मांग अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु जनसभा में पुलिस की मार व गोली का शिकार होकर घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहे थे। बिहार मिलट्री पुलिस ने घायलों को अस्पताल ने निकाल कर खड़ा कर गोली मारी थी। उन दिनों एस पी सिंहभूम डा० रामेश्वर उरांव हुआ करते थे ।इस

शहीद दिवस पर अन्य अनेक नेताओं ने गुआ पहुंचकर शहिदों को श्रद्धांजलि अर्पित की ।

झारखंड सरकार के मंत्री बिरूवा ने महत्वपूर्ण विचार रखते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी झारखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी सम्मान दिया जाए। आंदोलनकारियों का सबसे पहले सम्मान देने का कार्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही शुरू किया है। वे जब 2014 में पहली बार एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने गुवा आकर शहीदों के परिजनों को नौकरी देने का कार्य किया। मंत्री बिरुवा ने कहा कि गुवा गोलीकांड के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके संघर्ष और त्याग ने समाज को न्याय और अधिकार की लड़ाई के लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी पेंशन योजना का जो शुरुआत हुआ है, उसमें आंशिक संशोधन हुआ वह भी मुख्यमंत्री की देन है। जिन्होंने आंदोलनकारी को सम्मान देने का काम किया। वे सोमवार को गुवा में गुवा गोलीकांड के शहीदों को नमन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार में सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने झारखंड को अग्रणी राज्य के रूप में लाने का कार्य हो रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से झारखंड राज्य की एक अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना लागू कर गरीबों को घर देने का काम

किया। सर्वजन पेंशन योजना चालू किया, मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की जिससे सभी आहर्ताधारी 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 2500 रुपया प्रतिमाह की राशि सम्मान स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना इस योजना के माध्यम से 2026 तक पूरे झारखंड में बिजली पहुंचाने का कार्य मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे लोग जो 200 यूनिट तक बिजली जला नहीं पाते हैं, वैसे लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कार्य किये जा रहे हैं। विगत दिनों 15 हजार से भी अधिक सड़कों का मुख्यमंत्री ने पक्कीकरण कराने का कार्य किया है। ऐसे और भी सड़के हैं, जिसे आरसीसी मैं कन्वर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानकी मुंडाओं के लिए मुख्यमंत्री ने न्याय पंच का सर्वप्रथम सेरेंगसिया में उद्घाटन करके एक नई शुरुआत किया गया हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि सभी मिलकर झारखंड राज्य को आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। गुवा गोलीकांड शहादत दिवस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने शहीदों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के शिलापट पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। परिसम्पतियों का हुआ वितरण : कार्यक्रम में मंत्री और विधायक द्वारा नक्सली हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के 04 आश्रित सहित अनुकम्पा के आधार पर 06 आश्रितों को चतुर्थ वर्ग अनुसेवी के पद पर नियुक्ति दी गई। साथ ही सर्वजन पेंशन योजना, उन्नति का पहिया साइकिल वितरण, व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण, फूलों झानो आशीर्वाद योजना, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। ये थे उपस्थित : आयोजित कार्यक्रम में मझगांव के विधायक निरल पूर्ति, खरसावां के विधायक दशरथ गागराई, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू एवं मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, पुलिस उपमहानिरीक्षक कोल्हान रेंज अनुरंजन क्रिस्टोपोट्टा, उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक पश्चिम सिंहभूम राकेश रंजन सहित जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे

नई शिक्षा नीति में गरीब बच्चों की अनदेखी की गई है और उच्च शिक्षा का सपना टूटने वाला है

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : विभिन्न शिक्षा नीतियों में गरीब बच्चों की उपेक्षा की जा रही है। उच्च शिक्षा पाने के उनके सपने को कुचला जा रहा है। पहले शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। अब आरोप लग रहे हैं कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अन्वेषा योजना को बंद करने की योजना है।ओडिशा अभिभावक संघ ने इसका कड़ा विरोध करने की घोषणा की है। ओडिशा अभिभावक संघ ने पूछा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के आने के बाद निजी स्कूलों में आदिवासी बच्चों की शिक्षा कैसे बंद हो जाएगी। इस बीच, अन्वेषा योजना बंद होने से हजारों अभिभावक इस बात को लेकर गहरी चिंता में हैं कि वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में कैसे भेजेंगे। जिन स्कूलों ने बिना दस्तावेज वाले बच्चों को दाखिला दिया था, वे अब भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें देने में असमर्थ हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत उचित कदम नहीं उठाए गए, तो मासूम आदिवासी बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक ज़ोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा, ऐसा अभिभावक संघ ने कहा है।

इस बीच, मानवाधिकार आयोग ने लोक शिक्षा सचिव को आरटीई पारदर्शी पोर्टल में अनियमितताओं पर 23 तारीख तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अभिभावक संघ ने पूछा है कि जिन अभिभावकों के फॉर्म भरते समय दस्तावेज़ सही थे, उनके आवेदन कैसे खारिज कर दिए गए। आरोप लगाया गया है कि छात्रों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। कई फॉर्म निवास प्रमाण पत्र के आधार पर खारिज कर दिए गए हैं। जो निर्धारित नियमों के अनुसार है, अभिभावकों ने सही दस्तावेज़ जमा किए हैं। इसलिए इसे अस्वीकार करने से बच्चा अपने वाजिब अधिकारों से वंचित हो जाएगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कार्यवाहक अध्यक्ष प्रसन्ना बिशोयी ने कहा। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का कहना है कि हर बात पर चर्चा और विचार-विमर्श हो रहा है। छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। आरटीई हो या अन्वेषा, हर बात के क्रियान्वयन पर चर्चा हो रही है। इसलिए बच्चों के हित में इसे कितना लागू किया जाएगा, इस पर नज़र रखी जा रही है।

कई घटनाएं सामने आई हैं जहां बिजेड़ी पार्टी के भीतर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजद के शामिल न होने का राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, यह बहस का विषय है। कई घटनाएँ सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।जहां बीजद सत्ता में थी, वहां कोई किसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, अब सत्ता गंवाने के बाद कोई किसी के प्रति सम्मान नहीं दिखा रहा है। पिछले कुछ महीनों में बद्री पात्रा, प्रफुल्ल मल्लिक, रणेंद्र प्रताप स्वैन, देबाशीष सामंत्रे, भूपिंदर सिंह, शशिभूषण बेहरा और अरुण साहू जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं की टिप्पणियों ने अक्सर बीजद को मुश्किल स्थिति में डाला है। यहां तक कि पूर्व बीजद विधायक और वर्तमान बांकी विधायक देबिरंजन त्रिपाठी के पिता पार्वती त्रिपाठी द्वारा कहे गए शब्दों को भी नहीं भूलना चाहिए। सत्ता के समय में, जिसने भी पार्टी या बीजद नेतृत्व के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल घोष थे। लेकिन विपक्ष के सीट लेने के बाद ऐसी बड़ी कार्रवाई का कोई उदाहरण क्यों नहीं है? क्या बीजद के भीतर विद्रोह का डर है, जिसके कारण उपर्युक्त नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की

जा रही है? ऐसे सवाल सार्वजनिक रूप से पूछे जा रहे हैं।

रायगडा जिले के दो वरिष्ठ नेताओं ने बीजद छोड़ दिया है। पूर्व सांसद एन. भास्कर राव और पूर्व विधायक लाल बिहारी हिमिरिका ने मंगलवार को बीजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पांडियन का पार्टी में बने रहना आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023